दुनिया के मजदूरो एक हो!

बिगुल

मासिक बुलेटिन • अंक 10
फरवरी 1997 • दो रुपये • आठ पृष्ठ

पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट: एक और मजदूर विरोधी कमीनी हरकत

• सम्पादक

पांचवे वेतन आयोग की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट ने समाज के अलग-अलग वर्गों के प्रति वही रवैया अपनाया है, जिसकी उदारीकरण के दौर में अपेक्षा की जाती थी।

टाटा, बिड़ला, साहू जैन आदि बड़े पूंजीपतियों के अखबारों और उनके टुकड़खोर अर्थशास्त्रियों ने खुशी और सन्तोष प्रकट करते हुए कहा है कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें उदारीकरण के दौर में, अंतरराष्ट्रीय अर्थतंत्र के साथ एकीकृत हो जाने के लिए आतुर भारतीय अर्थतंत्र की जरूरतों और तकाज़ों के सर्वथा अनुरूप है। बुर्जुआ पार्टियों और चुनावी वामपंथी दलों से जुड़े ट्रेड यूनियनों ने भुनभुनाकर और मिनमिनाकर अपना असंतोष प्रकट किया है और रस्मी तौर पर विरोध में आंदोलन-प्रदर्शन आदि की चेतावनी दी है। पर इस वास्तविकता से भला कौन परिचित नहीं है कि यह एक गीदड़भभकी और छलपूर्ण दिखावे से अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन दलों से इन ट्रेड यूनियनों की गांठ जुड़ी हुई है, वे ही संयुक्त मोर्चा सरकार के साझीदार हैं।

आइये, सबसे पहले तो यह देखें कि पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर किसको क्या मिलेगा!

वेतन-वृद्धि के तमाम अखबारी शोर-शराबे के पीछे की सच्चाई यह है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों-मजदूरों को वास्तव में कुछ भी नहीं हासिल हुआ है जबकि अधिकारियों को काफी फायदा मिला है। फिलहाल जिस कर्मचारी का बेसिक वेतन 750 रुपये है, उसे कुल 2,160 रुपये मासिक प्राप्त होते हैं। पांचवे आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन संशोधन के बाद उसे कुल 2,440 रुपये और आवास भत्ता हासिल होगा। इसके ठीक विपरीत, एक अफसर, जिसका बेसिक वेतन 8,000 है,

उसके मासिक वेतन की कुल रकम वेतन संशोधन के बाद 16,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जायेगी। वेतन आयोग की इन सिफारिशों से ग्रुप-डी के कर्मचारियों को महज 13 प्रतिशत का लाभ मिल रहा है जबकि अफसरों के लिए यह लाभ 62.5 प्रतिशत है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन के रूप में 3,440 रुपये की मांग की थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 2440 रुपये की सिफारिश की है।

वेतन आयोग की इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसने निचले दर्जे के कर्मचारियों की भरती को 'फ्रीज' कर देने का प्रस्ताव किया है। यह रोजगार बढ़ाने के साझा सरकार के वायदे के विपरीत और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को जन्म देगा। अर्थवादी ट्रेड यूनियनों के नौकरशाह नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि सरकार धीरे-धीरे चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के दर्जे को ही समाप्त कर देना चाहती है या नाममात्र के स्तर पर ला देना चाहती है तथा इन सेवाओं को ठेके पर देकर इनका निजीकरण कर देना चाहती है। इससे बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों को सेवाक्षेत्र और केन्द्रीय उपक्रमों से भी लाभ निचोड़ने का अवसर तो हासिल होगा ही, बिचौलियों-दलालों का तबका भी काफी तेजी से फलेगा-फूलेगा और लाभ कमोयगा।

वेतन आयोग की इस रिपोर्ट ने हूबहू वैसी ही सिफारिशें की हैं, जिनके लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन (पूर्ववर्ती गैट) लगातार दबाव डालते रहे हैं और नुस्खे सुझाते रहे हैं। इन सिफारिशें का स्पष्ट अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी निकालने और उसकी भूमिका को घटाते जाने की प्रक्रिया को तेज करना, फालतू और अनुपयोगी बनाकर भारी मेहनतकश आबादी के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बन्द कर देना, कार्यालयों का आधुनिकीकारण और कम्प्यूटरीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफा कमाने का अवसर देना और सेवा क्षेत्र में शोषण की दर बढ़ा देना तथा ज्यादा से ज्यादा संगठित श्रम-शक्ति को 'कंट्रैक्ट जॉब' के जरिए निजीकरण करके बिखरा देना, उनकी मोल-तोल की क्षमता को गिरा देना और पूंजीपतियों को उन्हें ज्यादा से ज्यादा चूसने का खुला मौका देना। नौकरशाही को अधिक सुविधाएं दी गई

(पेज 5 पर जारी)

अफसरों के लिए मलाई, कर्मचारियों-मजदूरों के साथ धोखा, धांधली और धूर्तता

निजीकरण के खिलाफ पूरी दुनिया में जारी है मजदूरों की लड़ाई

• अरविन्द सिंह

निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ पूरी दुनिया में मजदूर संघर्षों की राह पर हैं। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां मजदूरों ने खुली पूंजीवादी लूट की इन नीतियों को बेखटके लागू होने दिया हो। यह बात अलग है कि नेतृत्व की अवसरवादिता और समझौतापरस्ती के चलते मजदूरों की ये लड़ाइयां सत्ताधारियों को फिलहाल कोई निर्णायक चुनौती नहीं दे पा रही हैं, लेकिन वे चैन की सांस भी नहीं लेने पा रहे हैं। पिछले दिनों एशिया के कई देशों से मजदूरों की ऐतिहासिक हड़तालों की खबरें मिली हैं।

इस्रायल में मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

नरसिंह राव और देवगौड़ा के इस्रायली बिरादर प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतान्याहू की सरकार द्वारा लगभग एक दर्जन सरकारी कम्पनियों को निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच देने, सामाजिक सेवाओं के मदों में कटौती करने, गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर नये कर थोपने और विवाहित मजदूर स्त्रियों की सेवा-सुविधाओं में कटौती के विरोध में लाखों मजदूरों ने ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल की।

हड़ताल का आह्वान 'हिस्ताद्रुत ट्रेड यूनियन फेडरेशन' ने किया था। इस ऐतिहासिक हड़ताल से समूचे देश

(पेज 6 पर जारी)

दक्षिण कोरिया में देशव्यापी मजदूर हड़ताल
मजदूरों ने "एशियाई शेर" के कान मरोड़े

साम्राज्यवादियों द्वारा तीसरी दुनिया के सामने विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला और "एशियाई शेर" के नाम से मशहूर दक्षिण कोरिया तेजी से एशियाई बकरी बनता जा रहा है। साम्राज्यवादी लुटेरों के टुकड़ों पर पलने वाले वहां के शासक वर्ग की आर्थिक नीति (जिसे आजकल भारत में नयी अर्थनीति के नाम से लागू किया जा रहा है) के दुष्परिणाम 1990 में ही आने शुरू हो गये थे। निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था का बुनियादी चरित्र होता है देश के प्राथमिक क्षेत्रों और समाज कल्याण योजनाओं का सत्यानाश करना। ऐसे में यदि निर्यात के पर्याप्त आर्डर मिलने बन्द हो जायें तो जो तबाही फैलती है कि आम आदमी को एक रोटी भी मिलना कठिन हो जाता है। समृद्धि के शिखर पर बैठा देश पल भर में भिखारी बन जाता है।

1995 में दक्षिण कोरिया का व्यापार घाटा 10 अरब डालर था, 1996 में यह बढ़कर दूना अर्थात 20 अरब डालर हो गया। इस गति से यदि यह बढ़ता गया तो स्थिति कभी भी खतरनाक बिन्दु तक पहुंच सकती है ठीक ऐसे ही वक्त में वहां के शासक वर्ग ने इस स्थिति से उबरने के लिए एक और गलत निर्णय लिया, जैसा कि पूंजीपति वर्ग करता है। मुनाफे की दर सुरक्षित रखने के लिये पूंजीपति वर्ग श्रमिकों के मेहनत की लूट को बढ़ाता जाता है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने मजदूरों की श्रम शक्ति को और राक्षसी तरीके से निचोड़ने के लिए नया श्रम कानून वहां की पार्लियामेण्ट द्वारा विपक्ष की अनुपस्थिति में 26 दिसम्बर को पास करवा करके लागू कर दिया। नये कानून ने मालिकों के लिए मजदूरों की छंटनी आसान बना दी, काम के घन्टों को मनमाने तरीके से बढ़ाने का अधिकार दे दिया, अड़तालीस कर्मचारियों को निकालकर नये कर्मचारी रखने का अधिकार दे दिया और प्रबन्धकों को मजदूर संघों में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार

(पेज 6 पर जारी)

आपस की बात

●

सम्पादक महोदय लाल सलाम

दिल्ली में कहीं से आपका क्रान्तिकारी पेपर बिगुल मई 1996 अंक मिला।

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और जिम्मेदारियां। चुनाव और सुधार के भ्रमजालों से बाहर आओ, नई समाजवादी क्रान्ति की ज्वाला भड़काओ! मई 1886 का रक्तरंजित दिन इत्यादि लेख क्रान्तिकारी ओज से भरपूर विचार पढ़ें।

हम कुछ साथी भी क्रान्तिकारी विचारों 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा' के पक्षधर है तथा ट्रेड यूनियन फ्रंट पर जे.सी.टी व शुगर मिल्स में कार्य कर रहे हैं।

आपका पेपर अच्छा लगेा बिगुल का एक प्रति भेजें।

- का. महेश महषि,
महासचिव, दी गंगानगर शुगर मिल्स लि., 'इफ्टू कार्यालय' शुगर मिल गेट के सामने,
श्रीगंगानगर(राज.) - 335001

●

मैंने आपके मासिक 'बिगुल' का अंक नवम्बर-दिसम्बर अंक पढ़ा। हमें बहुत ही पसन्द आया। मैं भी आपके मासिक 'बिगुल' का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं। बिगुल के पहले के अंक भेज सकते हों तो भेजियेगा।

- कुलदीप सिंह
संतनगर, सिरसा, हरियाणा,

●

पिछले तीन-चार महीनों से बिगुल का अंक लगातार मिलता रहा। इस पत्र की वैचारिक स्पष्टता तथा मजदूरों और किसानों के प्रति बेबाक प्रतिबद्धता ने प्रभावित किया। वैचारिक शून्यता और फैलायी जा रही अपसंस्कृति के माहौल में इस तरह के पत्रों की नितान्त आवश्यकता है। बिगुल का अंक नियमित भेजिएगा।

सियाराम शर्मा
शासकीय महाविद्यालय उतई,
पो. उतई, जिला - दुर्ग
मध्य प्रदेश - 491107

●

आपका पत्र मिला। बिगुल के अंक लगातार मिलते हैं।

MMSF (महाराष्ट्र मेडिकोज़ एंड साइंटिस्ट्स फ्रंट) का यहां विद्यार्थियों, डाक्टरों के बीच काम है। हमारे बुलेटिन से आपको इस फ्रंट के काम का अंदाजा होगा। हमारे संपर्क बम्बई और पूना में हैं।

कामगार क्षेत्र में म्युनिसिपल कारपोरेशन के कर्मचारियों के बीच हम लोग चर्चाएं रखते हैं। बस्तियों में युवा संगठन, दलितों के बीच सम्पर्क भी हैं।

बम्बई के विभिन्न मा-ले ग्रुपों के साथ मिलकर हम लोग एनरान, कान्ट्रेक्ट कामगार पद्धति जैसे मुद्दों पर मुहिम चला चुके हैं।

हमारी पत्रिका Quest का अगला बुलेटिन भेज रहा हूं।

- प्रशान्त भट्ट, बम्बई

●

मुझे आपके द्वारा सम्पादित पत्र 'बिगुल' का नवम्बर-दिसम्बर अंक अच्छा लगा। आपने इसमें अक्टूबर क्रान्ति के बारे में विस्तार से बताया है तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ढांचे पर भी विस्तृत प्रकाश डाला है।

कृपया मुझे 'बिगुल' का अगला अंक भेजना सुनिश्चित करें तथा इसका नियमित ग्राहक बनायें

- के. के. मिश्रा
पंजाब नेशनल बैंक,
सआदतगंज, लखनऊ

पाठक साथियों से

- बिगुल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके अधिक से अधिक ग्राहक बनायें।
- कारखानों, वर्कशापों, दफ्तरों के गेट पर बिगुल बेचें।
- बिगुल के लिए अधिक से अधिक चन्दा जुटाकर भेजें।
- इसके लेखों पर अपने और अपने साथियों के विस्तृत विचार लिखकर भेजें जिससे हम इसे और सुधार सकें।
- अपने इलाके के मजदूरों की समस्याओं और उनके संघर्षों पर रिपोर्टें भेजें।

'बिगुल ' की प्रतियों और 'बिगुल सहयोग कूपन ' के लिए हमें इस पते पर पत्र लिखिए

सम्पादक 'बिगुल'
द्वारा, ओ.पी. सिन्हा
69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड,
निशातगंज, लखनऊ – 226 007

बाल मजदूर राजनारायण का
असली हत्यारा कौन है?

मुनाफाखोरी की हवस इंसान को शैतान बना देती है। ऐसे ही शैतानों ने बांदा जिले में एक चौदह साल के मजदूर बच्चे की बर्बरतापूर्वक जान ले ली।

चौदह वर्षीय राजनारायण बांदा जिले के बबेरू कस्बे में स्थित एक दाल मिल में पिछले पांच-छह महीने से काम कर रहा था। रोज की तरह राजनारायण पिछले 12 दिसम्बर को भी काम पर आया। उस दिन चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मिल मालिक और मैनेजर ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। राजनारायण अपनी सफाई देता रहा, लेकिन मालिक और मैनेजर नहीं माने। पिटाई के बाद उसके दोनों हाथ और गले में फंदा लटकाकर छत से लटका दिया गया और चोरी का माल पूछने के लिए तीन-चार बाल्टी ठण्डा पानी उसके ऊपर फेंक दिया गया। पानी फेंकने से गले का फंदा कस गया और देखते-देखते राजनारायण की सांसें उखड़ गयीं।

अपने साथी मजदूर की इस नृशंस हत्या से उत्तेजित मजदूरों ने तुरन्त काम बंद कर दिया और मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ साथियों ने राजनारायण के घर खबर पहुंचायी।

राजनारायण के पिता देव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट पर मिल मालिक और मैनेजर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद से मिल मालिक और मैनेजर दोनों फरार हैं। हो सकता है कि पुलिस इस मामले में मुस्तैदी दिखाये और राजनारायण के हत्यारों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाये, लेकिन इससे राजनारायण की जिन्दगी तो वापस मिलने वाली नहीं। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि न तो राजनारायण अकेला है और न ही उसके मालिक और मैनेजर जैसे लोग ही अकेले हैं। न जाने कितने राजनारायण मुनाफाखोर नरपिशाचों के हाथों रोज-रोज कत्ल किये जा रहे हैं आखिर कब तक रुकेगा इन कत्लों का सिलसिला? इन कातिलों की असली सज़ा क्या है?

असली कातिल तो मुनाफाखोरी और निजी सम्पत्ति पर टिकी यह समूची पूंजीवादी व्यवस्था है। हर रोज, हर घण्टा, हर क्षण न जाने कितने लोगों की बलि लेकर भी इसकी रक्तपिपासा शान्त नहीं होती। जब तक यह पूतना जिन्दा रहेगी, राजनारायणों का खून पीती रहेगी।

(बिगुल संवाददाता)

हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दोस्त कौन है? यह सवाल क्रान्ति में सर्वाधिक महत्व का सवाल है।... क्रान्तिकारी पार्टी आम जनता की रहनुमा होती है, और ऐसी कोई भी क्रान्ति कभी सफल नहीं हो सकती जिसमें क्रान्तिकारी पार्टी जनता को गलत राह पर ले जाए। इस बात की गारण्टी करने के लिए कि हम अपनी क्रान्ति में जनता को गलत राह पर न ले जाएं और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें, हमें अपने वास्तविक दुश्मनों पर हमला करने के लिए अपने वास्तविक दोस्तों के साथ एकता कायम करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

● माओ त्से-तुङ

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

(1) 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आवादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मज़दूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मज़दूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

(2) 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

(3) 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को यह नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

(4) 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर ''कम्युनिस्टों'' और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा ही कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

(5) 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आहानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

बिगुल यहां से प्राप्त करें

- शहीद पुस्तक़ालय, द्वारा डा० दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, मर्यादपुर, मऊ
- जनचेतना, जाफरा बाजार, गोरखपुर
- विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, गोरखपुर
- विश्वनाथ मिश्र, चेतना कार्यालय, बड़हलगंज, गोरखपुर–273402
- ओमप्रकाश, बाबा का पुरवा (पुराना), पेपर मिल रोड़, निशातगंज, लखनऊ
- जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, लखनऊ, (शाम 5 से 7)
- सत्यम वर्मा, यूनीवार्ता, काज़मी चैम्बर्स, 5 पार्क रोड, लखनऊ
- राहुल फाउण्डेशन, 3/274, विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
- डा. डी०के०. सचान, (शस्य वैज्ञानिक), A–308 आवास विकास (गंगापुर), रामपुर–244901
- प्रो. प्यारे लाल, 139, फूलबाग कालोनी, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर–263145
- राजेन्द्र प्रसाद, रेनु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, रेणुकूट, सोनभद्र
- अमृतलाल पाण्डेय, निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसखारी, जि० – अम्बेडकरनगर
- एतकाद अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ फाउण्डेशन आफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- संतोष शर्मा, Q-No -L/61K, बरौनी रेलवे कालोनी, बरौनी, बेगूसराय
- चन्द्रकेतु नरायण शर्मा, एडवोकेट, सांचीपट्टी, बागगली गाछी, स्थान--पो–हाजीपुर, जि–वैशाली
- दीपशिखा पत्रिका मंडप, द्वारा श्री शिवदास पाण्डेय, पानी टंकी चौकी, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर
- मैत्रेयी साहित्य संगम, सर्वे आफिस के सामने, लालबाग के.डी.एस. दरभंगा–846004
- अविनाश कुमार सिन्हा/रणजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा शैलेन्द्र श्रीवास्तव, बरियारी चक, मेंहसी, पूर्वी चम्पारण
- जनार्दन थापा, लुकसान बाज़ार, पो.कैरन जि. जलपाई गुड़ी – 735205
- डा.हरियश राय, ए–205 सुजल अपार्टमेंट, सेटेलाइट रोड, रामदेव नगर, अहमदाबाद–380054
- पुस्तक–पत्रिका बिक्री–वितरण केन्द्र डिल्ली बाजार चढ़ाव के पास (निकट पदम कन्या स्कूल), काठमांडू
- विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाईन, बुटवल, लुम्बिनी, नेपाल
- जलजला पुस्तक सदन, धमवोजी चौक, नेपालगंज बांके, नेपाल

कपड़ा मजदूरों का गला घोंटती नयी अर्थनीति

• ओमप्रकाश

6 फरवरी, 1997 को गुजरात हाईकोर्ट ने वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले ने वहां की सरकार को गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन को पूरी तरह बन्द करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। वहां के 17 कारखानों में कार्यरत 14000 मजदूरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम पर जबरन निकाल दिया जायेगा।

गुजरात जो इस देश के कपड़ा उद्योग में पहला स्थान रखता था, और लाखों मजदूरों को आजीविका प्रदान करता था, 1980 से धीरे-धीरे कमजोर होते हुए अंतिम तौर पर समाप्त हो गया। इस क्षेत्र की सारी पूंजी वहां के पूंजीपति पहले ही निकालकर अन्य धन्धों में लगा चुके थे अब बन्द कारखानों की जमीनें बेचकर और मालामाल होंगे। रह गये कुछ लाख बेकार मजदूर और उनका परिवार और तन ढंकने भर को कपड़ा न पाने वालों की आबादी; तो उन्हें "राष्ट्रहित" के नाम पर हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी वहां की सरकार का यही मानना है कि मेहनतकश अवाम में देश प्रेम का पर्याप्त अभाव है तथा वे अनैतिक हैं जिससे देश का काफी अहित हो रहा है। कपड़ा मिलों को बन्द करके उन्होंने मजदूरों को "राष्ट्रप्रेम" "नैतिकता" का सबक दिया है। कितना पुण्य कार्य है? इस पुण्य कार्य में गुजरात हाईकोर्ट ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिक का पुण्य कमाने का संयुक्त मोर्चा अब मजदूरों की लाशों के ऊपर से होकर गुजरेगा। 6 फरवरी '97 का निर्णय तो मात्र एक शुरुआत है!

बिगुल के पाठकों को याद होगा कि अभी कुछ ही महीनों पूर्व उत्तर प्रदेश में पॉच कताई मिलें बन्द कर दी गयीं और करीब 10,000 मजदूर सड़क पर आ गये। इसके पहले दर्जनों बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलें बन्द की जा चुकी थीं और इसके परिणामस्वरूप कताई मिलों को देर-सबेर बन्द करना ही था। इसके अतिरिक्त देश के हर हिस्से में -- आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, पं बंगाल, पांडिचेरी, मध्यप्रदेश आदि में भी यही काम साथ-साथ चल रहा है। 1980 से आज तक बन्द होने वाली कपड़ा मिलों और कताई मिलों की संख्या सैकड़ों में है और बेकार हुए मजदूरों की संख्या कई लाख है। पहले तो यह काम अलग-अलग कारखानों को धीरे से बन्द करके किया जाता था, लेकिन अब 6 फरवरी 97 के बाद इस निर्मम कार्य को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद, गुजरात की ही तरह एकमुश्त और एक झटके में किया जायेगा। मजदूरों की अपील के सारे रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। 1982 में देश की कपड़ा मिलों में 4.2 अरब वर्ग मीटर कपड़ा पैदा किया जाता था और 1995 में यह घटकर 1.9 अरब मीटर तक पहुंच गया है। यही रफ्तार जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में इस उद्योग का नामोनिशान मिट जायेगा। क्या इस देश में कपड़े की जरुरत समाप्त हो गयी है? नहीं। उत्पादित कपड़ा तो पहले ही बहुत कम पड़ता था। और आबादी एवं पूंजीवाद के विकास ने तो इसकी आवश्यकता और बढ़ा दी है। 1982 में जितने कारखाने थे आज उससे कई गुना अधिक की जरुरत है। फिर यह उल्टी धारा क्यों चल रही है! इसके कई महत्वपूर्ण कारण है।

इसके लिये जरूरी है कि हम एक नजर भारत के कपड़ा उद्योग के इतिहास पर डालें। कपड़ा उद्योग इस देश का परम्परागत उद्योग रहा है। मुर्शिदाबाद के कपड़े पूरे यूरोप पर छाये रहते थे। इसी कपड़ा उद्योग को लूटकर और तबाह करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद इस देश में स्थापित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर नयी तकनीकी के आधार पर कपड़ा उद्योग का पनपना शुरू होता है और इसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम तेज़ पड़ता जाता है। चरखा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। 1920 से 1947 तक कपड़ा मिलों के मजदूरों की राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में प्रमुख बनी रही। ये मजदूर आर्थिक मांगों के लिए कम देश की आजादी के लिए अधिक लड़े। 1946 के देशव्यापी हड़ताल में इनकी भूमिका अहम थी। 6 जनवरी 1947 को कानपुर कपड़ा मिलों के मजदूरों पर पुलिस की गोलीबारी से आठ मजदूर शहीद हुये। इस घटना ने मजदूर आंदोलन के साथ छात्रों, किरानियों, दस्तकारों को जोड़ दिया। अपने आर्थिक हितों के लिए लगातार आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल आदि चलाने के साथ ही आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद होने वालों में काफी बड़ी संख्या कपड़ा मजदूरों की थी।

संघर्ष और कुर्बानी की इन शानदार परम्पराओं की जमीन पर खड़ा था यहां का कपड़ा मजदूर। आजादी के समय इनका जोश इन्हें क्रांति की राह पर आगे बढ़ा रहा था, और यही खतरनाक था नये शासक वर्ग के लिए। इसके नेतृत्व ने शासक वर्ग से समझौता किया और लड़ाई की दिशा राजनीतिक संघर्षों से महज आर्थिक संघर्षों की ओर मोड़ दिया। नेतृत्व की इस ऐतिहासिक गद्दारी ने कपड़ा मजदूरों के जुझारूपन को इस शर्मनाक मंजिल तक पहुंचा दिया है।

कपड़ा उद्योग की इस हालत को ज़रा नई आर्थिक नीति और आर्थिक उदारीकरण की नजर से देखें तो बात और साफ हो जायेगी। उदारीकरण की नई नीतियों की शुरुआत प्रकारांतर से 1980 में ही हो चुकी थी। ठीक एक वर्ष बाद ही 1981 में दत्ता सामंत के नेतृत्व में जबरदस्त हड़ताल की शुरुआत हो जाती है। इन आर्थिक नीतियों की मुख्य बात यह थी कि यह विश्व पूंजीवाद में ढांचागत ठहराव और मंदी के दौर में पैदा हुई। इसका उद्देश्य था कि कैसे मरणासन्न पूंजीवाद की हिफाजत की जाये और मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी चरित्र को कमजोर किया जाये। जहां तक पूंजीवाद के हिफाजत का सवाल है, उसके लिए यह जरूरी है कि सारे उत्पादक गतिविधि के दौरान पूंजीपति को मिलने वाली मुनाफे की निश्चित दर बनी रहे और विकसित होती रहे। पुरानी कपड़ा मिलों में (सरकारी और गैर सरकारी दोनों), पुरानी तकनीक और श्रम केन्द्रित प्रकृति होने के कारण, मुनाफे की दर लगातार गिरती जा रही थी जो पूंजीवाद के हितों के अनुरूप नहीं था। ऐसे में इन मिलों को बन्द करके इनका पैसा अधिक मुनाफे वाले मिलों में लगाना पूंजीवाद के आम हित में था। साथ में बंद मिलों की जमीन-जायदाद बेचने पर अलग से भी लाभ था। बम्बई की 1981 की हड़ताल ने पूंजीपतियों को मिलें बन्द करने का अच्छा मौका दिया। यहीं दत्ता सामंत की नीतियां मजदूर वर्ग की नहीं, पूंजीपति वर्ग के हित में जाकर खड़ी हो गयी। नई अर्थ नीति ने पहली बार कम मुनाफे की दर वाले मिलों को बन्द करने की ठोस योजना दी और उसे लागू किया गया। तब से आज तक कपड़ा मिलों के बन्द होने का सिलसिला रुका नहीं।

यहां पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में ये नीतियां एशियाई विकास बैंक के सहयोग से तैयार की गयी थी। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और कम मुनाफे वाली फैक्टरियों को बन्द करने की योजना को समायोजन कार्यक्रम का नाम दिया गया। इन नीतियों को लागू करने के लिए गुजरात राज्य को एक अरब डालर का कर्ज एशियन विकास बैंक से मिला। इन नीतियों का दूसरा पहलू जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह कि पूरे संगठित क्षेत्र को ही विकेन्द्रित करके पूरे देश में फैला दिया जाये। पूंजीपति वर्ग ने अतीत की क्रान्तियों का समाहार करके यह नतीजा निकाला था कि संगठित क्षेत्र के मजदूर ही क्रान्ति का अगुआ दस्ता बनते हैं, यदि यह क्षेत्र ही विघटित कर दें तो क्रान्ति से कुछ समय तक बचा जा सकता है। कपड़े का उत्पादन विकेन्द्रित क्षेत्र में 1981 में 5.5 अरब मीटर से बढ़कर 1995 में 18.5 अरब मीटर तक हो गया। लगभग तीन गुने की वृद्धि। विकेन्द्रित क्षेत्र में पूंजीपति को कई फायदे हैं, यहां पर चूंकि कोई मजदूर कानून नहीं काम करता है और मजदूर वर्ग बंटा होता है इसलिए उसकी श्रमशक्ति को न्यूनतम मूल्य पर निचोड़ना आसान हो जाता है। उत्पादन के इस क्षेत्र के मजदूरों की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है।

लेकिन इसी तरह के उत्पादन से पूंजीवाद चल ही नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि बड़े कारखाने जरूर खड़े किये जायें। कपड़ा क्षेत्र में भी कुछ नये अत्याधुनिक कारखाने खड़े किये गये। आधुनिक मशीनों में बहुत कम लोगों को लगाकर अति उत्पादन किया जा रहा है। चूंकि यहां पर कार्यरत मजदूर बहुत कम हैं इसलिए उन्हें सामान्य बाजार दर से अधिक मजदूरी देकर खरीदा जा सकता है, और उनके सर्वहारा चरित्र को नष्ट किया जा सकता है। इसके कई उदाहरण हमारे आस-पास मौजूद हैं।

भारत के कपड़ा उद्योग में होने वाले परिवर्तन पूरी तरह नई आर्थिक नीतियों से तालमेल बनाये हुए हैं। ऐसे में मजदूर वर्ग के संघर्ष का निशाना नई अर्थनीति होनी चाहिए और लक्ष्य एक वैकल्पिक आर्थिक-सामाजिक संरचना की स्थापना होना चाहिए। पिछले दिनों देश की तमाम चुनावी पार्टियों से जुड़े मजदूर संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति गठित करके कपड़ा मजदूरों के हितों के लिए लड़ाई शुरू की गयी। पिछले महीने इसी समिति के नेतृत्व में रेल रोको और रास्ता जाम कार्यक्रम लिया गया। संघर्ष में मजदूरों ने जोरदार शिरकत की और देश के कई हिस्सों में रेल यातायात पूर्णतः बन्द हो गया। अफसोस, इस आंदोलन में एक भी राजनीतिक मांग या नई अर्थनीति को पलटने की मांग नहीं थी। सिर्फ बकाये वेतन का भुगतान, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में बेहतर दाम की बात ही मुख्य थी। कारण साफ है। सभी चुनावी राजनीतिक पार्टियों ने तो संसद में इन नीतियों के सामने घुटने टेक रखा है। अब तो सिर्फ मजदूरों को लेफ्ट-राइट कराना है। ठीक इसीलिए एक माह बीतने भी न पाया था कि गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और सारी मांगे धरी की धरी रह गयीं।

हम कहना यह चाह रहे हैं कि आज का मरणासन्न पूंजीवाद श्रमिक वर्ग को किसी प्रकार की रियायत देने की औकात ही खो चुका है। धीरे-धीरे सारे उद्योगों पर इन नीतियों का आक्रमण शुरू हो चुका है। अब हर रोज हजारों मजदूर अपनी नौकरी से हाथ धोयेंगे। चूंकि कपड़ा उद्योग के मजदूरों के साथ संघर्षों की एक शानदार परम्परा जुड़ी हुई है, अतः उन्हें सोचना होगा कि अब दुअन्नी-चवन्नी की लड़ाई का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब तो लड़ाई पूंजीवाद के खात्मे की है। भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका की शानदार परम्परा को पुनर्जीवित करके एक बार फिर से उन्हें इस आर्थिक नवउपनिवेशवाद की कब्र खोदने के काम में पहलकदमी लेनी होगी। यह उनका ऐतिहासिक दायित्व है।

•

राजनीतिक संघर्ष का संगठन.....

(पृष्ठ 4 का शेष)

के निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव या संकल्प पेश करने के जरिए उन्हें इस आन्दोलन को बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे खुद को संघर्षरत जन समुदाय का सचेत सदस्य और वर्ग-दुश्मनों के खेमे में उनके हितों का प्रवक्ता समझें तथा जिम्मेदार पदाधिकारी और पार्टी-कार्यकर्ता समझें।

यदि पार्टी की समस्त शक्तियों की एकताबद्ध और संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ कार्रवाइयां चंद हफ्तों के अंदर हमारी मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में और लगातार बढ़ती तादाद में प्रस्ताव मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती हैं तो हमारी पार्टी का यह गंभीर सांगठनिक कार्यभार होगा कि वह हमारी मांगों के प्रति समर्थन प्रकट करने वाले जन समुदाय को जत्थेबंद कर ले। यदि आंदोलन ने एक विशेष ट्रेड यूनियन चरित्र अपना लिया हो तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसे प्रयास किये जायें जिससे ट्रेड यूनियनों में हमारा सांगठनिक प्रभाव बढ़ जाये।

इस लिहाज से ट्रेड यूनियनों के भीतर काम करने वाले हमारे ग्रुपों को, स्थानीय ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ पूरी तैयारी के आधार पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी चाहिए जिससे या तो इन नेताओं का प्रभाव ही समाप्त हो जाये और नहीं तो ये हमारी पार्टी की मांगों के आधार पर एक संगठित संघर्ष छेड़ने के लिए बाध्य हो जायें। जहां कहीं भी फैक्ट्री कौंसिलें, औद्योगिक कमेटियां या ऐसी अन्य संस्थाएं मौजूद हैं, वहां हमारे ग्रुपों को इनके पूर्णाधिवेशनों (प्लेनरी मीटिंग) को इसके लिए प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वे संघर्ष का समर्थन करने के पक्ष में फैसला लें। यदि कई एक स्थानीय संगठनों को, कम्युनिस्ट नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग द्वारा चलाये जा रहे महज रोजी-रोटी के आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रभावित किया जा चुका हो तो फिर उन सबको आम सम्मेलनों में एकत्र किया जाना चाहिए जिनमें फैक्ट्री-मीटिंगों के विशेष प्रतिनिधि भी शामिल हों, और ऐसे सम्मेलनों में आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किये जाने चाहिए।

(अगले अंक में जारी)

दस्तावेज

कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढांचा

(1921 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत ''कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन पर प्रस्ताव'')

(पांचवी किश्त)

•

व्ला०इ०लेनिन

पेरिस कम्यून से लेकर अबतक के वर्ग–संघर्षों के इतिहास की सबसे बुनियादी शिक्षाओं में से एक यह है कि अपनी एक सच्ची क्रांतिकारी पार्टी – एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के बिना सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध अपनी लड़ाई को फैसलाकुन जीत की मंजिल तक कदापि नहीं पहुंचा सकता और समाजवाद की स्थापना कदापि नहीं कर सकता।

लेनिन ने पहली बार, समग्र रूप में एक क्रांतिकारी सर्वहारा पार्टी के निर्माण एवं गठन तथा स्वरूप एवं प्रकृति से संबंधित सिद्धान्त प्रतिपादित किये। मेंशेविकों और काउत्स्की से लेकर खुश्चेव तक और आज के सी०पी०आई०, सी०पी०एम० तथा सी०पी०आई०(एम०–एल०) (लिबरेशन) जैसे संशोधनवादियों तक सभी नकली कम्युनिस्ट जो क्रांति के लक्ष्य के साथ विश्वासघात करके महज पूंजीवादी चुनावी राजनीति और अर्थवाद के दलदल में धंस गये, कम्युनिस्ट पार्टी के सांगठनिक सिद्धान्तों को तोड़–मरोड़कर पेश करते हैं या भुला देते हैं। क्रांति से विमुख हो चुके लोगों को भला एक क्रांतिकारी पार्टी की क्या जरूरत? उन्हें लेनिन, स्तालिन और माओ की पार्टियों जैसी पार्टी की नहीं, चवन्निया मेंबरी वाली, महज खुली चुनावी पार्टियों की जरूरत होती है। उन्हें मजदूरों की आर्थिक मांगों और राजनीतिक अधिकारों की मांगों के लिए नहीं बल्कि महज ट्रेडयूनियनवाद के लिए ट्रेडयूनियनों की दुकानों की ज़रूरत होती है।

चिन्ता की बात यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले बहुतेरे क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ग्रुप भी आज सांगठनिक सिद्धान्तों और व्यवहार के मामले में बेहद ढिलाई बरत रहे हैं। बोल्शेविक सांगठनिक ढांचा खड़ा करने के बारे में वे गंभीर नहीं दीखते और ढीला–ढाला सामाजिक जनवादी आचरण कर रहे हैं।

एक सही–सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी के पुनर्गठन के लिए सांगठनिक उसूलों पर अडिग रहना बुनियादी विचारधारात्मक महत्व का मुद्दा है। एक सही क्रांतिकारी सांगठनिक ढांचे के बगैर कोई पार्टी सही कार्यक्रम होने पर भी क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सकती। आज ज़रूरत है कि वर्ग–सचेत सर्वहारा वर्ग को और कम्युनिस्ट कतारों को बोल्शेविक सांगठनिक उसूलों से एक बार फिर परिचित कराया जाये।

इस उद्देश्य से हम 'बिगुल' में विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बहुमूल्य दस्तावेज का किश्तों में प्रकाशन कर रहे है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस द्वारा पारित इस दस्तावेज का मसविदा स्वयं लेनिन ने तैयार किया था। इन आम सिंद्धान्तों की लोकप्रिय व्याख्या बाद में स्तालिन ने भी अपनी पुस्तक 'लेनिनवाद के मूल सिद्धान्त' में की। – सम्पादक

V. राजनीतिक संघर्ष का संगठन

राजनीतिक अभियान कैसे चलाये जायें

31. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब उसका पार्टी संगठन राजनीतिक कार्रवाई नहीं कर सके। प्रत्येक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति का, और इन परिस्थितियों में पैदा होने वाले सभी मौकों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, सांगठनिक रणनीति और रणकौशल विकसित किये जाने चाहिए। पार्टी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी वह सुव्यवस्थित ढंग से चलाये जाने वाले और कुशलतापूर्वक संगठित उग्र परिवर्तनवादी (रैडिकल) प्रचार के द्वारा उत्तेजनकारी राजनीतिक घटनाओं या समूचे अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाली व्यापक हड़तालों का लाभ उठा सकती है। एक बार यदि पार्टी किसी परिस्थिति-विशेष का इस्तेमाल करने का फैसला ले ले तो उसे अपने सभी सदस्यों और पार्टी इकाइयों की ऊर्जा इस अभियान में केन्द्रित कर देनी चाहिए।

इसके अलावा, पार्टी अपने केन्द्रकों और मज़दूर ग्रुपों के काम के जरिए जो भी सम्पर्क बनाती है, उन सबका इस्तेमाल राजनीतिक महत्व के केन्द्रों पर जनसभाएं आयोजित करने और हड़तालों के अनुवर्ती कामों (फॉलो-अप) के लिए किया जाना चाहिए। पार्टी [illegible]क्ताओं को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वे श्रोताओं को यह विश्वास दिला दें कि केवल कम्युनिज़्म ही उनके संघर्ष को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचा सकता है। पार्टी के विशेष आयोगों को इन मीटिंगों की पूरी तैयारी करनी चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से पार्टी खुद अपनी मीटिंगें आयोजित न कर सके तो उसे हड़तालियों द्वारा या संघर्षरत सर्वहारा वर्ग के किसी भी अन्य हिस्से द्वारा आयोजित आम सभाओं को संबोधित करने के लिए उपयुक्त कामरेडों को जरूर भेजना चाहिए।

जहां कहीं भी इस बात की संभावना हो कि किसी मीटिंग के बहुमत को या उसके एक बड़े हिस्से को हमारी मांगों के समर्थन के लिए राजी किया जा सकता हो, तो इन मांगों को भली भांति सूत्रबद्ध कर लिया जाना चाहिए और मंजूरी के लिए पेश किये जाने वाले प्रस्तावों और संकल्पों के पक्ष से सही-सटीक ढंग से दलीलें पेश की जानी चाहिए। यदि ऐसे प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो हरचंद कोशिश यह होनी चाहिए कि उसी मसले पर उसी जगह या दूसरी जगह होने वाली सभी मीटिंगों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे प्रस्ताव या संकल्प स्वीकार किये जायें या कम से कम एक मजबूत अल्पमत द्वारा उनका समर्थन किया जाये। इस तरह से हम आंदोलन में मेहनतकश अवाम को जत्थेबंद करने में सफल हो सकेंगे, उसे अपने नैतिक प्रभाव के अंतर्गत ला सकेंगे और उसके बीच अपने नेतृत्व को मान्यता दिला सकेंगे।

ऐसी मीटिंगों के बाद, जिन कमेटियों ने इनकी सांगठनिक तैयारियों में भाग लिया हो और ऐसे अवसरों का लाभ उठाया हो, उन्हें पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटी के सामने पेश करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तथा अनुभवों या संभावित गलतियों से, भविष्य के लिए उचित नतीजे निकालने के लिए, सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। हर ऐसी परिस्थिति-विशेष के अनुसार मज़दूरों की व्यावहारिक मांगों को लेकर पोस्टर, पर्चे और इश्तहार निकाले जाने चाहिए, उन्हें मज़दूरों के बीच बांटकर इन मांगों का प्रचार किया जाना चाहिए और उनकी खुद की मांगों के जरिए उनके बीच यह साबित कर दिया जाना चाहिए कि किसतरह से कम्युनिस्ट नीतियां उनकी परिस्थिति से मेल खाती हैं तथा उनपर लागू होती हैं। पोस्टरों के सही बंटवारे के लिए तथा उनको लगाने के लिए उपयुक्त स्थान और उचित समय का चुनाव करने के लिए विशेष रूप से संगठित ग्रुपों की आवश्यकता होती है। पर्चों का वितरण कारखानों के अंदर या उनके सामने तथा उन सभाभवनों में होना चाहिए जहां मजदूर इकट्ठा होते हैं। पर्चों के वितरण के साथ-साथ आकर्षक नारे लगाये जायें और बहसें की जायें, जिससे बातें मेहनतकश अवाम के हर आदमी के दिमाग में बैठ जायें। विस्तार से लिखे गये पर्चे भरसक सभाभवनों, कारखानों, रिहाइशी जगहों या ऐसे ही अन्य स्थानों पर बांटे जाने चाहिए जहां लोग छपी हुई चीजों को उचित रूप से ध्यान देकर पढ़ सकें।

इस प्रकार के प्रचार के साथ-साथ संघर्ष के दौरान ट्रेड यूनियन की तमाम मीटिंगों और कारखानों की सभी मीटिंगों में समान्तर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस तरह की मीटिंगों में, उपयुक्त वक्ताओं और बहस करने वालों को जन समुदाय के सामने हमारे दृष्टिकोण की व्याख्या करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चाहे ये मीटिंगे हमारे कामरेडों द्वारा बुलाई गई हों या फिर अन्य किसी कारण से हमारे अनुकूल हों। हमारी पार्टी के अखबारों को इस प्रकार के विशेष आंदोलनों की खबरों तथा उनके पक्ष में दिये गये अच्छे तर्कों को छापने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। वास्तव में पूरे पार्टी संगठन को, कुछ समय के लिए, इसप्रकार के आंदोलन के सामान्य उद्देश्य की सेवा में सन्नद्ध कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारे कामरेड अनथक शक्ति के साथ काम कर सकें।

कारखानों के केन्द्रकों पर आधारित सचल नेतृत्व और संगठन सफल प्रदर्शन की कुंजी है!

32. प्रदर्शनों के लिए अत्यन्त सचल और आत्मत्यागी नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो किसी विशेष कार्रवाई के लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़संकल्प हो और किसी भी समय यह आंकने की क्षमता रखता हो कि अमुक प्रदर्शन अपनी उच्चतम संभव प्रभावकारिता तक पहुंच चुका है या उस विशेष परिस्थिति में जनता के किसी कदम -- प्रदर्शन, हड़ताल या अंततोगत्वा आम हड़तालों के जरिए आंदोलन को आगे विस्तारित करके और अधिक घनीभूत किया जा सकता है। युद्ध के दौरान शांति के लिए किये गये प्रदर्शनों ने हमें सिखाया है कि ऐसे प्रदर्शनों के विसर्जित हो जाने के बाद भी, यदि वह प्रश्न वास्तविक महत्व का हो और व्यापक जन समुदाय के लिए उसके और अधिक दिलचस्पी का प्रश्न बन जाने की संभावना हो, तो एक सच्ची सर्वहारा पार्टी को, चाहे वह कितनी छोटी या गैरकानूनी क्यों न हो, न तो अपने रास्ते से हटना चाहिए और न ही चुप बैठना चाहिए। सड़कों पर किये जाने वाले प्रदर्शन तभी अधिकतम प्रभावी हो पाते हैं जब उन्हें बड़े कारखानों के आधार पर संगठित किया जाता है। जब हमारे केन्द्रकों (न्यूक्लियस) और कार्यकर्ता ग्रुपों ने मौखिक और पर्चों के माध्यम से किये गये प्रचार के द्वारा काफी अच्छी तैयारी करके किसी परिस्थिति-विशेष में विचार और कार्रवाई की एक निश्चित एकता हासिल कर ली हो, तब प्रबंधक कमेटी को कारखानों के गुप्त पार्टी सदस्यों, और केन्द्रकों तथा कार्यकर्ता ग्रुपों के नेताओं का एक सम्मेलन, निर्धारित तिथि पर आयोजित होने वाली मीटिंग का समय एवं कार्यक्रम तय करने के लिए तथा साथ ही, नारे तय करने और आंदोलन को घनीभूत करने की संभावनाओं, उसे समाप्त करने या तितर-बितर करने के समय आदि के बारे में फैसला लेने के उद्देश्य से बुलाना चाहिए। प्रदर्शन का मेरुदण्ड, निश्चत तौर पर, सुप्रशिक्षित, अनुभवी और लगनशील पदाधिकारियों का ग्रुप होना चाहिए जो कारखानों से प्रदर्शन के आरम्भ होने से लेकर प्रदर्शन के विसर्जित होने के समय तक जनसमुदाय के साथ घुला-मिला रहे।

जिम्मेदार पार्टी कार्यकर्ताओं को जन समुदाय के बीच व्यवस्थित ढंग से बिखेर दिया जाना चाहिए ताकि पदाधिकारीगण एक-दूसरे से सक्रिय सम्पर्क बनाये रख सकें और आवश्यक राजनीतिक निर्देश देते रह सकें। प्रदर्शन के इस तरह के सचल और राजनीतिक तौर पर संगठित नेतृत्व के होने से ही यह प्रभावी ढंग से संभव हो पाता है कि ऐसे प्रदर्शनों को लगातार नये-नये रूप दिये जा सकें और उनके परिणामस्वरूप ये घनीभूत होकर और बड़े स्तर की जन-कार्रवाई का रूप ले सकें।

मज़दूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों का संगठन तथा सुधारवादियों का अलगाव

33. जो कम्युनिस्ट पार्टियां अन्दरूनी तौर पर दृढ़ हैं, जिनमें तपे-तपाये पदाधिकारियों की एक टुकड़ी मौजूद है और जनता के बीच जिसका पर्याप्त आधार मौजूद है, उन पार्टियों को व्यापक अभियान चलाकर मजदूर वर्ग के गद्दार समाजवादी नेताओं के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर देने और कम्युनिस्ट झण्डे तले मेहनतकश जन समुदाय की बहुसंख्या को गोलबंद करने की हरचंद कोशिश करनी चाहिए। अभियानों को विभिन्न तरीकों से इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठित किया जाना चाहिए कि परिस्थिति सचमुच वास्तविक लड़ाई के अनुकूल है, या अभी अस्थायी ठहराव का काल चल रहा है। यदि परिस्थिति सचमुच वास्तविक लड़ाई के अनुकूल हो तो कम्युनिस्ट सक्रिय हो जाते हैं और अपने को सर्वहारा आंदोलन की अगली कतार में खड़ा कर लेते हैं।

ऐसी कार्रवाईयों के लिए सांगठनिक पद्धतियों का चुनाव करते समय पार्टी की अन्दरूनी बनावट भी एक निर्णायक उपादान के रूप में काम करती है।

मिसाल के तौर पर, जर्मनी में सर्वहारा वर्ग के सामाजिक रूप से निर्णायक हिस्सों को जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में जो कि एक नई जन-पार्टी थी, ला खड़ा करने के लिए तथाकथित ''खुला पत्र'' प्रकाशित करने का तरीका इस्तेमाल किया गया था जो कि अन्य देशों की तुलना में वहां के लिए अधिक कारगर था। यह तरीका अपनाकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़ती हुई निराशा और तीखे होते हुए वर्ग-संघर्षों के काल में गद्दार समाजवादी नेताओं को बेनकाब करने के लिए सर्वहारा वर्ग के अन्य जन संगठनों को संबोधित किया जिसका उद्देश्य यह था कि पूरे सर्वहारा वर्ग के सामने उनसे साफ-साफ पूछा जाये कि क्या वे (गद्दार समाजवादी नेता) सर्वहारा वर्ग की स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली बर्बादी के खिलाफ और उसकी छोटी से छोटी मांग के लिए भी, यहां तक कि रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भी अपने तथाकथित शक्तिशाली संगठनों को साथ लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर संघर्ष के मैदान में आने को तैयार हैं?

कम्युनिस्ट पार्टी जहां कहीं भी इस तरह के अभियान की शुरुआत करती है तो उसे अपनी ऐसी कार्रवाई की पहुंच मज़दूर वर्ग की व्यापक आबादी तक बनाने के लिए मुकम्मिल तौर पर सांगठनिक तैयारियां कर लेनी चाहिए।

कारखानों के सभी पार्टी ग्रुपों और पार्टी के ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों को चाहिए कि वे पार्टी द्वारा उठाई गई मांगों पर, जो कि सर्वहारा वर्ग की सबसे जरूरी मांगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपनी अगली फैक्ट्री या ट्रेड यूनियन मीटिंगों में तथा सभी सार्वजनिक सभाओं में भी, इसतरह की मीटिंगों के लिए पूरी तैयारी करके, बहस करवायें। जन-समुदाय की अनुकूल मानसिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए सभी जगहों पर पर्चे, इश्तिहार और पोस्टर बांटे जाने चाहिए। जहां हमारे न्यूक्लियस और ग्रुप जन समुदाय को हमारी मांगों के पक्ष में ला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हों, उन सभी जगहों पर यह काम असरदार ढंग से होना चाहिए। हमारे पार्टी-प्रेस (यानी पार्टी की पत्रिकाओं व प्रकाशनों को) को, ऐसे अभियान के समूचे दौर में आंदोलन की समस्याओं पर, रोजाना लिखे गये छोटे-बड़े लेखों के जरिए, हर संभव दृष्टिकोण से समस्या के हर पहलू से देखते हुए, लगातार प्रकाश डालना चाहिए। संगठन को चाहिए कि ऐसे लेखों के लिए वे पार्टी की पत्रिकाओं को लगातार मसाला देते रहें और इस बात पर गहरी नज़र रखें कि पार्टी के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयास में पत्रिकाओं के सम्पादकगण कहीं पीछे न छूट जायें। ऐसे संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के संसदीय ग्रुपों और म्युनिसिपल प्रतिनिधियों को भी व्यवस्थित ढंग से काम करना चाहिए। विभिन्न संसदीय निकायों में पार्टी नेतृत्व

(पेज 3 पर जारी)

पांचवे वेतन आयोग की मज़दूर विरोधी कमीनी हरकत.....

(पेज 1 से जारी)

है, क्योंकि सरकार को अब बेहतर 'आफिस ऑटोमेशन' के माहौल में काम करने वाली योग्य नौकरशाही की जरूरत है। इसीलिए बड़े पूंजीपतियों के अखबार इसे बदलते समय और आर्थिक उदारीकरण के माहौल के अनुरूप नौकरशाही की 'स्ट्रीमलाइनिंग' की संज्ञा दे रहे है और तालियां बजा-बजाकर, किलक-किलककर खुशी प्रकट कर रहे हैं। उन्हें एक फायदा और भी है। वेतन आयोग की इन सिफारिशों के लागू होने के बाद भी केन्द्र सरकार के अफसरों की अपेक्षा निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अफसरों का वेतन व अन्य सुविधाएं बहुत अधिक रहेंगी। आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 10 बिलियन डालर की पूंजी के सालाना आने की आशा की जा रही है। इसका एक निहितार्थ यह भी है कि अधिकारियों के लिए निजी क्षेत्र की सेवा शर्तें सार्वजनिक क्षेत्र से फिर भी काफी बेहतर बनी रहेगी। कुण्ठित सरकारी अधिकारी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में और अधिक गहरे धंसते जायेंगे और सरकार को, देशी पूंजीपतियों को तथा साम्राज्यवादियों व अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों को निजीकरण एवं उदारीकरण के पक्ष में एक और तगड़ा साक्ष्य व तर्क प्राप्त हो जायेगा। जहां तक मजदूरों का सवाल है, उनकी संगठित शक्ति को अभी ही काफी हद तक बिखराया जा चुका है और ट्रेड यूनियनों के सुविधाभोगी, मौकापरस्त नेतृत्व को विश्वास में लेकर उनके हितों पर एक के बाद एक करके कई कुठाराघात पहले ही किये जा चुके हैं। पांचवे वेतन-आयोग की रिपोर्ट उनपर एक और फैसलाकुन चोट है। सरकारी कारखानों-कार्यालयों में भी अब ज्यादा काम ठेके पर ही कराया जायेगा। स्वचालन और कंप्यूटरीकरण द्वारा भारी श्रम-शक्ति को बेकारों की रिजर्व सेना में तब्दील कर देने और कम संख्या में और बिखरे हुए रूप में काम करने वाले मज़दूर वर्ग के शोषण की दर को बहुत अधिक बढ़ा देने तथा मजदूरों के एक ऊपरी हिस्से को सफेदपोश, कुलीन और सुविधाभोगी बनाकर क्रान्तिकारी कतारों से अलग कर देने का रास्ता साफ किया जा चुका है। जैसा कि होता रहा है, केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लेने के साथ ही राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा देंगी।

वेतन आयोग की यह रिपोर्ट मज़दूरों के हितों के कितने खिलाफ है, इसका एक अहम सबूत यह भी है कि पूंजीपतियों के अखबारों और संस्थाओं ने इसका एक स्वर से स्वागत किया है। उन्हें यदि असंतोष है तो यह कि सरकार और अधिक तेजी से इस दिशा में आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाती। सरकार को भी ऐसा करने में भला क्या एतराज होता? पर उसे तो यह भी खयाल रखना है कि खौलते जन असंतोष को तरह-तरह की तरकीबों से कैसे रोका जाये। पूंजीवादी व्यवस्था के दूरगामी हितों का भी उसे ध्यान रखना है और चुनावी राजनीति के तकाजों का भी। इसलिए यह एक-एक कदम करके भारतीय मेहनतकश जनता को आर्थिक नवउपनिवेशवाद के नागपाश में जकड़ने का काम कर रही है। गौर कीजिए, साहू-जैन घराने का भोंपू 'टाइम्स आफ इण्डिया' (नई दिल्ली) वेतन आयोग की इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए अपने 1 फरवरी 1997 के सम्पादकीय में क्या लिखता है!

उक्त सम्पादकीय के अनुसार, "निश्चित ही यह अतीत से एक स्वागतयोग्य प्रस्थान है, बशर्ते कि सरकार इस रिपोर्ट को एक तदर्थ कदम के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक और मानवशक्ति -- दोनों के प्रबंधन की एक व्यापक रणनीति के श्रीगणेश के रूप में लागू करे।" यह उक्ति अपने आप में पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट के धुर जनविरोधी चरित्र को दिन के उजाले की तरह साफ कर देती है।

और अंत में, हम अपनी बात जागरूक, सचेत मजदूर वर्ग और उनके सच्चे प्रतिनिधियों को उनके उन्हीं महत्वपूर्ण कार्यभारों और चुनौतियों की याद दिलाते हुए समाप्त करेंगे। पहली बात तो यह कि मजदूर हितों पर और व्यापक आम जनता के हितों पर आज नई अर्थनीति, संरचनागत समायोजन, उदारीकरण-निजीकरण या भूमण्डलीकरण के नाम पर जो चोट की जा रही है, वह एक या दो कारखानों, या यहां तक कि एक या दो देशों की भी बात नहीं है। यह पूरी दुनिया के स्तर पर हो रहा है। विशेषकर भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों की मेहनतकश जनता को साम्राज्यवादी देश, यहां के देशी पूंजीपतियों को जूनियर पार्टनर बनाकर आर्थिक नवउपनिवेशवादी नागपाश में जकड़ रहे हैं। इस नये दौर में, हर जगह, एक बार फिर श्रम और पूंजी एकदम आमने-सामने खड़े हो रहे हैं। लातिन अमेरिकी देशों से लेकर इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया आदि एशियाई देशों तक मज़दूर उभारों का अनवरत सिलसिला जारी है। भारत में भी असंतोष का लावा सुलग रहा है।

दूसरी बात जो गांठ बांधने की है, वह यह कि उदारीकरण-निजीकरण के दौर में छंटनी-तालाबंदी-वेतन-जाम और नई नौकरियों पर रोक के खिलाफ लड़ाई एक या दो या चार कारखानों में अलग-अलग नहीं लड़ी जा सकती। इस विश्वव्यापी और देशव्यापी लहर को रोकने और फिर उसका मुंह मोड़ने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को और निजी क्षेत्र के मजदूरों को एक साथ खड़ा होना होगा।

तीसरी बात यह कि अब यह लड़ाई इतिहास के जिस मोड़ पर लड़ी जा रही है, उस समय यह सच्चाई एकदम साफ है कि पूरी अर्थनीति के खिलाफ, इसे लागू करने वाली राज्यसत्ता के खिलाफ मोर्चा बांधे बिना आज आर्थिक रियायतें हासिल करने की भी एक सीमा है। मजदूर वर्ग को आज अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा।

इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंत में जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वहारा वर्ग के सभी जन संगठनों को एक "खुला पत्र" लिखकर बढ़ती हुई निराशा और तीखे होते हुए वर्ग संघर्षों के काल में संबोधित किया था जिसका उद्देश्य पूरे सर्वहारा वर्ग को यह बताना था कि क्या गद्दार समाजवादी नेता, अर्थवादी और ट्रेड यूनियनवादी नेता मेहनतकश अवाम की स्पष्ट दिखलाई पड़ने वाली बर्बादी के खिलाफ और उसकी छोटी से छोटी मांग के लिए भी यानी रोटी के चंद टुकड़ों के लिए भी अपने तथाकथित देशव्यापी शक्तिशाली संगठनों को लेकर संघर्ष के मैदान में आने को तैयार हैं अथवा नहीं! उससमय काउत्स्की के सामाजिक जनवादी सुविधाभोगी चेले-चपाटियों के प्रभाव के कारण जर्मन सर्वहारा वर्ग ने रोज़ा लक्ज़ेमबुर्ग और लीब्क्नेख्त के साथ खड़े सच्चे कम्युनिस्टों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इसका ऐतिहासिक दण्ड उसे हिटलर और नात्सीवाद के दमन-चक्र के रूप में मिला।

भारत का मजदूर वर्ग भी यदि खतरे की संकेतों की ओर ध्यान देकर क्रांतिकारी एकजुटता और लामबंदी की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के बजाय मजदूर वर्ग के नकली रहनुमाओं के पीछे-पीछे चलता रहेगा तो आने वाले समय में उसे इसका खामियाजा बर्बर बुर्जुआ निरंकुशशाही या फासिस्टतंत्र के कहर के रूप में भुगतना पड़ेगा। उसे भारतीय "आम्स्टर्डमपंथियों" से -- ज्योतिबसु, सुरजीत, इन्द्रजीत गुप्त और चतुरानन मिश्र के "वामपंथ" को समझना होगा जिनके समर्थन व भागीदारी से चल रही साझा सरकार एक के बाद एक मजदूर-विरोधी कदम उठाते जाने में राव सरकार को भी दो कदम पीछे छोड़ चुकी है। उसे बी.एम.एस., एच.एम.एस, इण्टक न सही सीटू, एटक जैसों के नेताओं से तो सवाल करना ही होगा कि क्या ये तथाकथित देशव्यापी यूनियनें उनकी रोजी-रोटी की छोटी से छोटी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं या सिर्फ भिखमंगई ही इनका पेशा बन चुकी है।

भारत की विडम्बना तो यह है कि यहां सच्चे सर्वहारा क्रान्तिकारी भी खण्ड-खण्ड में बंटे हुए हैं और वे फिलहाल एकजुट होकर सर्वहारा वर्ग के लिए तत्काल एक चेतावनी जारी करने की स्थिति में भी नहीं हैं, हालांकि "बढ़ती हुई निराशा और तीखे होते वर्ग संघर्ष" का वर्तमान काल 1920-30 से भी कहीं अधिक कठिन है। अतः सर्वहारा वर्ग के सच्चे ईमानदार प्रतिनिधियों के सामने भी चुनौतियां बहुत कठिन हैं।

इस समय सबसे पहला जरूरी कार्यभार यह है कि सच्चे सर्वहारा क्रान्तिकारी ग्रुप व संगठन नये सिरे से एकजुटता व सांगठनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही, लेनिन की शिक्षा पर अमल करते हुए, "आम मेहनतकशों की ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचने के लिए मुकम्मिल सांगठनिक तैयारियां" करें और तरह-तरह के अभियान संगठित करें। उन्हें अपनी कम ताकत में भी मजदूर वर्ग के रोजमर्रा के संघर्षों में शिरकत करनी होगी तथा प्रत्येक संघर्ष की अगली कतारों में रहने की और फिर नेतृत्व देने की कोशिश करनी होगी। उन्हें आंशिक मांगों के लिए लड़ना सीखना होगा और फिर आंशिक संघर्षों से समन्वित संघर्षों की ओर आगे बढ़ना होगा। सुधारवादी और अर्थवादी नेताओं को महज सुधारवादी और अर्थवादी कहते रहने के बजाय, लेनिन के ही कहे मुताबिक, ठोस ढंग से उनका पर्दाफाश करना होगा। इसके लिए मजदूर आबादी के साथ एकजुट होकर आर्थिक संघर्षों के साथ ही लगातार राजनीतिक अभियान चलाने होंगे, क्रांतिकारी प्रचार कार्य चलाना होगा और इस बात पर सूक्ष्म और चौकस निगाह रखनी होगी कि तीव्र संकट के समय घटनाक्रम को प्रभावित किया जा सके। इसके लिए आज जैसे दौर में एक क्रांतिकारी मजदूर अखबार की बेहद-बेहद जरूरत है, बुनियादी जरूरत है और अनिवार्य जरूरत है। अपनी क्षमता और संसाधनों की बेहद-बेहद कमी के बावजूद हम 'बिगुल' को ऐसे ही सांचे में ढालना चाहते हैं।

हमें आने वाले विस्फोटक समय की कठिन चुनौतियों का जिस हद तक भी अहसास बना है, उसे हम हर मजदूर के दिल की गहराइयों में उतार देना चाहते हैं।

वेतन आयोग की मुख्य-मुख्य बदमाशियां

1. वेतन आयोग में बैठे हुए पूंजीवाद के टुकड़खोरों ने एक सबसे बड़ी बदमाशी यह की है कि नई नौकरियां पैदा करने की जगह केन्द्र सरकार के उपक्रमों-प्रतिष्ठानों के साढ़े तीन लाख रिक्त पदों को भी खाली रखने की सिफारिश की है। गौरतलब बात यह भी है कि ये रिक्तियां 1983 में जो पद स्वीकृत हुए थे, उसके हिसाब से हैं। इस हिसाब से देखें तो वास्तव में, 13 वर्षों बाद, आबादी की बढ़ती जरूरतों, विकास और सेवाओं के विस्तार को देखते हुए रिक्त पदों की संख्या साढ़े तीन लाख के बजाय दस लाख के आसपास होनी चाहिए।

और यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर, वेतन आयोग ने जो कमीनगी की है वह यह कि आगामी इस वर्षों में नौकरियों में तीस प्रतिशत कटौती कर देने की सिफारिश की है। यानी आटोमेशन और कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर मजदूरों-कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की जायेगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से पूंजी निकालने, उन्हें निजी पूंजीपतियों को सौंपने तथा सेवा क्षेत्र के भी निजीकरण की गति तेज कर दी जायेगी। जहां तक पैर पसारते निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय उपक्रमों का सवाल है, वे भी अधिक मुनाफा निचोड़ने के लिए ज्यादातर अत्याधुनिक उद्योग ही लगायेंगे जिनमें नौकरियों की संख्या बहुत कम होगी। साथ ही, भारत जैसे गरीब देशों की सस्ता श्रम शक्ति का दोहन करने के लिए जो श्रम-संकेंद्रित उद्योग लगेंगे, उनमें ज्यादा काम ठेके के मजदूरों से, दिहाड़ी पर या कैजुअल मजदूरों से कराये जायेंगे। देवगौड़ा सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में तो ज्यादा नौकरियां पैदा करते हुए निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों को लागू करने की बात की थी। अब जब वह ठीक उल्टी दिशा में चल रही है तो खुद को "वामपंथी" कहने वाले सुरजीत, ज्योतिबसु, इन्द्रजीत गुप्त, चतुरानन मिश्र और उनके लग्गू-भग्गू सीटू-एटक के ट्रेडयूनियन नौकरशाह क्या कर रहे हैं? वे इस सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं?

2. वेतन आयोग के बुर्जुआ मुर्दरिसों की दूसरी मजदूर-विरोधी कमीनी चाल यह है कि उन्होंने 'गोल्डेन हैण्डशेक' के नाम पर होने वाली छंटनी को पूरी मंजूरी देने के 'जनरल एक्जिट पॉलिसी' की भी सिफारिश की है। यानी मज़दूरों की "फाजिल" संख्या को कम करने के लिए उन्हें अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले ही प्राविडेण्ट फण्ड और हरजाने के तौर पर एकमुश्त कुछ रकम देकर छुटकारा पा लिया जायेगा। साथ ही, अब कारखाने बंद होने या निजीकरण की स्थिति में बेकार हो गये मजदूरों-कर्मचारियों को कहीं और खपाने की जिम्मेदारी से भी सरकार मुक्त हो जायेगी।

3. वेतन आयोग के शकुनि मामाओं ने साझा सरकार के कौरव-भाइयों को तीसरी कुटिल सलाह यह दी है कि रिटायरमेण्ट की उम्र साठ वर्ष कर दी है। इसके पीछे की सोच यह है कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऑटोमेशन-कम्प्यूटराइजेशन का काम पूरा होने तक पुराने हाथों से ही काम चला लिया जाये और उनकी अवकाश-प्राप्ति के बाद नई भरती की ही न जाये।

4. शकुनि मामाओं ने चौथा पांसा यह फेंका है कि यदि किसी के खिलाफ कोई विभागीय जांच की कार्रवाई चल रही हों, कोई अनुशासनिक कार्रवाई पेंडिंग हो या उसे विभागीय स्तर पर किसी रूप में दण्डित किया गया हो तो उसका बोनस रोकने या काट लेने का अधिकार प्रबंधन को देने की सिफारिश की है। यदि यह सिफारिश लागू कर दी जाती है तो यह लगभग वैसा ही काला कानून होगा, जिसके विरुद्ध पूरे दक्षिण कोरिया के मजदूर सड़कों पर उमड़ पड़े थे और उनका संघर्ष आज भी जारी है।

5. बोनस अबतक उत्पादन से जुड़ा हुआ था, अब उसके उत्पादकता से जोड़ दिया गया है उत्पादकता इस आधार पर मापी जाती है कि जितना 'इनपुट' या लागत है, उसका 'आउटपुट' यानी उत्पादन के साथ अनुपात क्या है (इसे इनक्रिमेण्टल इनवेस्टमेण्ट-आउटपुट रेशिओ कहा जाता है)। यह भी एक गहरी चाल है। फिलहाल कारखानों से कार्यालयों तक के ऑटोमेशन-कम्प्यूटराइजेशन और नई जरूरतों के हिसाब से 'इनपुट' आने वाले कुछ वर्षों तक लगातार अधिक रहेगा और इसतरह उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उपरोक्त हिसाब से उत्पादकता घटी हुई दिखाई देगी जिसके आधार पर सरकार मजदूरों का बोनस काट लेगी।

6. वेतन आयोग द्वारा जिस संशोधित वेतनभान की सिफारिश की गई है, उससे सिर्फ अधिकारियों को ही लाभ हुआ है। 8,000 बेसिक वेतन वाले अफसर को आज 16,000 रुपये मिलते हैं जो वेतन-संशोधन के बाद बढ़कर 26,000 रुपये हो जायेगा। दूसरी ओर 750 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी-मजदूर को आज 2,160 रुपये मासिक मिलते हैं, जो वेतन संशोधन के बाद 2,440 रुपये हो जायेगा।

अफसरों के लिए और भी बहुतेरी सुविधाओं की सिफारिश की गई है और सबसे अधिक लाभ आई.ए.एस. संवर्ग को दिया गया है। ज्वायण्ट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को एक टेलीफोन अटेण्डेण्ट रखने के लिए 15,00 रुपये अलग से देने की सिफारिश की गई है। 'टॉप एक्जक्यूटिव क्लास' के महामहिमों के लिए वेतन को 'रैंक' से 'डीलिंक' करने की सिफारिश की गई है यानी अब सरकार भी ऊपर के "योग्य" अधिकारियों को "रैंक" के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी योग्यता के हिसाब से मनमाना वेतन-भत्ते आदि दे सकेगी जैसा कि निजी क्षेत्र में होता है। दूसरी ओर क्लास-तीन और क्लास-चार के कर्मचारियों को एक साथ मिला देने की (जिसे 'ऑक्जिलियरी स्टॉक' कहा जायेगा) सिफारिश की गयी है जिसका असली मकसद है कि चौथी श्रेणी में भरती बंद कर दी जाये, नाममात्र का स्टॉक रखा जाये और उनका सारा काम ठेके पर कराया जाये।

पांचवे वेतन आयोग की इन सिफारिशों के बाद भारतीय मजदूर वर्ग से हमारा यही कहना है कि:

"अगर हम नहीं लड़ते
अगर हम लड़ते नहीं जाते
तो दुश्मन
अपनी संगीनों से हमें खत्म कर डालेगा
और फिर
हमारी हड्डियों की ओर इशारा करते हुए कहेगा
देखो : ये गुलामों की हड्डियां हैं
गुलामों की।"

नारी सभा

धीरे-धीरे आगे बढ़ती है

• जेम्स कोनाली

अपनी देह और आत्मा में जकड़ी हुई
सदियों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उठ खड़ी
उन औरतों का प्रयास
आज़ादी की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है
मजदूर वर्ग को अवश्य ही देना चाहिए साधुवाद
और जोरदार होनी चाहिए
उनकी वाहवाही
अगर दासता के खिलाफ उनकी नफरत और उमंग
आजादी की ओर बढ़ती है धीरे–धीरे
औरतों की सेना
लड़ाकू मजदूरों की सेना के आगे–आगे।

('आयरलैण्ड की पुनर्विजय' 1915 से यह कविता ली गई है। जेम्स कोनाली आयरिश क्रांतिकारी नेता थे, 1916 के डबलिन में इस्टर अभ्युत्थान के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी थी।)

क्रांति ने उन्हें ज़मीन दी और स्वतंत्र पहचान भी!

"कामरेड वाङ ने औरतों के नीचे दर्जे की मिसाल चौथी मोर्चा सेना तथा नयी चौथी सेना द्वारा मुक्तांचलों में भूमि-सुधार के दौरान अपने अनुभव की कहानी के जरिए पेश की। जब जमीन बांटी गयी, विवाहित औरतों को उसका हिस्सा मिला। मगर गरीब किसान-औरतों का कोई नाम नहीं था, उन्हें या तो 'फलां की पत्नी' या 'फलां की मां' के तौर पर दर्ज किया गया था अथवा उस मौके के लिए जल्दबाजी से कोई नाम दिया गया था। इस रूप में मुक्ति ने औरतों को उसके जमीन के साथ नाम भी दिया।"

(पीकिङ रिव्यू, संख्या 10,1973)

मजदूरों ने एशियाई शेर के कान मरोड़े.....

(पेज 1 से आगे)

दे दिया। इन सबके साथ एक नया सुरक्षा कानून बनाकर वहां की पुलिस को भी हड़ताली मजदूरों का निर्ममतापूर्वक दमन करने का अधिकार दे दिया गया। नये श्रम कानूनों से वहां की सबसे जुझारू यूनियन (सरकारी मान्यता प्राप्त यूनियन की प्रतिद्वंद्वी) की मान्यता भी सन् 2000 तक के लिए समाप्त कर दी।

पिछले कई वर्षों से अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए निरन्तर लड़ते आ रहे दक्षिण कोरियाई मजदूरों ने नये श्रम कानून के विरोध में तुरन्त हड़ताल शुरू कर दी। एक शहर से शुरू होकर देश के सभी हिस्सों तथा उद्योगों में हड़ताल की लहर फैल गयी। अठारह दिनों तक यह हड़ताल लगातार जारी रही। रशियाई शेर और उसके महाप्रभु अमेरिकी साम्राज्यवाद घुटने टेकने के लिए विवश होने लगे तथा यूनियन के नेताओं को नये श्रम कानून पर बातचीत के लिए आमंत्रण दिया गया। श्रमिकों ने एक मत से आमन्त्रण को ठुकरा दिया। उनका पक्ष था कि नये श्रम कानून पर कोई बात हो ही कैसे सकती है, क्योंकि उसे हम पूर्णतः खारिज करते हैं। पहले नये कानून को सरकार वापस ले फिर हम बात करें। "शेर" ने कान तो उमेठवा लिया लेकिन एकदम से घास खाना कैसे शुरू कर दे, और यदि "शेर" ही ऐसा करेगा तो तीसरी दुनिया के गीदड़ों (नई अर्थनीति के पैरोकारों) की तो शामत ही आ जायेगी।

18 दिन की लम्बी आम हड़ताल के बाद मजदूरों ने अपनी रणनीति बदली है। अब वे सप्ताह में एक दिन, प्रत्येक बुधवार को हड़ताल करते हैं। 15 जनवरी के बाद से यह क्रम लगातार जारी है और हड़ताल में शामिल मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के अनुसार 18 दिन की हड़ताल में सिर्फ आटो उद्योग में अकेले 16 करोड़ डालर का नुकसान हुआ। मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि नया श्रम कानून और नया सुरक्षा कानून वापस नहीं लिया गया तो 18 फरवरी से वे फिर अनिश्चित कालीन आम हड़ताल पर चले जायेंगे। सरकार और साम्राज्यवादियों की तमाम तिकड़मों के बावजूद संघर्ष कमजोर नहीं पड़ा है। जबरदस्त छात्र आन्दोलन तो दक्षिण कोरिया में कई वर्षों से चल रहा है और अब मजदूर आन्दोलन। ऐसे में यदि दोनों मिल जायें (जो असम्भव नहीं है) तो स्थिति विस्फोटक हो जायेगी।

इन संघर्षों का चाहे जो परिणाम हो एक बात स्पष्ट हो गयी है कि यदि दक्षिण कोरिया की अर्थ व्यवस्था इस तरह ध्वस्त हो सकती है तो भारत जैसे देश, जो उसी का अनुकरण कर रहा है कब तक टिकेगा? ऐसे में मजदूर आन्दोलन का स्वतःस्फूर्त तरीके से भड़क उठना अवश्यंभावी है और साथ में छात्र आन्दोलन भी। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ चलने वाला दक्षिण कोरियाई मजदूरों का बहादुराना संघर्ष तब तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, जबतक कि वे नये श्रम कानून के खिलाफ लड़ते-लड़ते समाजवाद के लिये लड़ने की राह पर आगे नहीं बढ़ते। यह कार्य सिर्फ मजदूर संघों के नेतृत्व में नहीं होगा बल्कि इसके लिए एक क्रान्तिकारी पार्टी का होना अनिवार्य है। एक क्रान्तिकारी विचारधारा की रोशनी में सिर्फ एक क्रान्तिकारी पार्टी ही मजदूरों, छात्रों और समाज के अन्य क्रान्तिकारी वर्गों के संघर्षों को एक कड़ी में पिरोकर व्यवस्था के क्रान्तिकारी रुपान्तरण के कार्य को अंजाम दे सकती है।

लेनिन और माओ त्से-तुङ की क्रान्तिकारी विचारों के बहुत करीब रही बहादुर कोरियाई जनता इस सच्चाई को निश्चित रूप से देर-सबेर समझेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले पांच वर्षों से चल रहे छात्र और मजदूर आन्दोलन के गर्भ में क्रान्ति का बीज पनप रहा हो। वैज्ञानिक तर्क-पद्धति ऐसी संभावना की ओर संकेत करती है।

-ओ.प्र.सिं.

निजीकरण के खिलाफ पूरी दुनिया में जारी मजदूरों की लड़ाई.....

(पेज 1 से आगे)

का जनजीवन ठप्प पड़ गया। सभी आवश्यक उपयोगी सेवाएं -- डाक एवं दूरसंचार, रेडियो प्रसारण, बैंक सड़क परिवहन व बन्दरगाह, स्वास्थ्य सेवाएं हड़ताल के कारण लगभग ठप्प पड़ गयी थीं।

इस्रायल के मजदूरों ने अमेरिकी सरपरस्त प्रधानमंत्री नेतानयाहू को इस जबर्दस्त सफल हड़ताल के जरिये चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में वह चैन की नींद नहीं सो पायेगा। हड़ताल से बौखलाए नेतान्याहू ने इसे "राजनीति से प्रेरित" बताया और कहा कि मजदूरों की यूनियन हिस्तादूत और विरोधी लेबर पार्टी के बीच नापाक सम्बन्ध है।

जहां तक हिस्तादूत और लेबर पार्टी के बीच रिश्तों का सवाल है तो इस पर इतना ही कहना काफी है कि मुट्ठीभर निहित स्वार्थी लेबर पार्टी के नेताओं के फुसलाने-बरगलाने से देश भर के लाखों मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकते। उनके पास खुद का अपना एक दिमाग है और वे अपना भला-बुरा समझ सकते हैं। वे यह जानते हैं कि लेबर पार्टी के नेता भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। वे उसी तरह विकल्पहीनता की स्थिति में हैं, जिस तरह भारत के मजदूर। लेकिन, जिस तरह हर रात की कोई सुबह होती है, उसी तरह विकल्पहीनता की यह काली रात भी एक दिन खत्म होगी ही। वह दिन निकट आता जा रहा है जब मजदूर इन मजबूरी के नेताओं से अपना पिण्ड छुड़ा लेंगे और सच्चे सर्वहारा नेतृत्व के साथ खुद को जोड़कर अपनी सच्ची आजादी खोये हुए रास्ते को ढूंढ़ लेंगे।

जनाब प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप बतायेंगे कि मजदूरों को राजनीति से प्रेरित क्यों नहीं होना चाहिए? शायद आप यह मानते हों कि राजनीति का खेल खेलना तो सिर्फ आप जैसे घाघों का काम है। "जाहिल-जपाट" मजदूरों को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नेतानयाहू जी आप भ्रम में हैं, मजदूर राजनीति सीख गये हैं। बहुत पहले ही वे हड़तालों की राजनीति सीख चुके हैं और यही नहीं हड़तालों से भी आगे बढ़कर वे सत्ता पर कब्जा करने और मजदूरों की सत्ता चलाने की राजनीति भी वे काफी पहले सीख चुके हैं। इसलिए, मजदूरों के राजनीति प्रेरित होने पर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्रीलंका में अनिश्चितकालीन मजदूर हड़ताल

श्रीलंका के मजदूरों ने निजीकरण के खिलाफ हड़ताल करके अपने सत्ताधारियों को सांसत में डाल दिया है। चाय कम्पनियों के निजीकरण के बाद श्रीलंकाई सरकार द्वारा स्टील कारपोरेशन को कोरिया के हेम जंग कारपोरेशन के हाथों बेच दिये जाने के विरोध में मजदूर संघर्ष के रास्ते पर उतर पड़े। पिछले 14 दिसम्बर से सरकारी स्टील कारपोरेशन के कामगार नये मालिकों को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये। सरकार ने कोरियाई कम्पनी को स्टील कारपोरेशन के 51 प्रतिशत शेयर बेच दिये हैं।

स्टील कारपोरेशन मजदूर यूनियन ने सरकार से इस सौदे को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री चन्द्रिका कुमारतुंगा ने मजदूर नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए यह चेतावनी दे दी थी कि निजीकरण की नीतियों में अड़ंगा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कुमारतुंगा के भाषण के कुछ ही घण्टे बाद 15 मजदूर नेताओं को आधी रात के समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब ये नेता मजदूरों के साथ कोरियाई अधिकारियों को अहाते में घुसने से रोक रहे थे।

अपने नेताओं की गिरफ्तारी से मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का ऐलान कर दिया। मजदूरों ने घोषणा की कि जब तक उनके नेताओं की रिहाई नहीं की जाती और कारखाने में तैनात एक हजार पुलिस बलों को तत्काल नहीं हटाया जाता वे काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने सरकार से यह मांग भी रखी कि कोरिया के अधिकारियों को कारखाने के अहाते में नहीं घुसने दिया जाये।

श्रीलंका के स्टील कारपोरेशन के मजदूरों की यह हड़ताल उस समय शुरू हुई जब विश्व बैंक का एक शिष्टमंडल कोलंबो में मौजूद था और श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बैठकर निजीकरण की नीतियों को लागू करने के रास्ते की अड़चनों की समीक्षा कर रहा था। श्रीलंकाई सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए विश्व बैंक के शिष्टमंडल ने भी बेहयाई के साथ यह बयान जारी किया कि श्रम संगठन निजीकरण के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। दुनिया के गरीब मुल्कों की अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने का ढोल पीटने वाली इस अन्तरराष्ट्रीय संस्था के अधिकारियों का यह बयान अपने आप ही उसके खूनी चेहरे को नंगा कर देता है। दुनिया भर के मजदूर विश्व बैंक के इस चेहरे को पहचान चुके हैं और बिना किसी भ्रम में आये वे अपने वाजिब हकों के लिए संघर्षों में कूद पड़े हैं।

श्रीलंकाई मजदूरों की इस शानदार हड़ताल का नतीजा क्या निकला, यह तो हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक नतीजा एकदम साफ है और वह यह कि श्रीलंकाई सरकार मजदूरों के ऊपर निजीकरण का पाटा बेखटके नहीं चला पायेंगे। आने वाले दिनों में जब श्रीलंकाई सरकार राष्ट्रीय विमान सेवा, एअर लंका और दूरसंचार उद्योगों आदि का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में हजार बार सोचेगी क्योंकि बहादुर श्रीलंकाई मजदूर चुपचाप नहीं बैठेंगे।

विद्रोही महाकवि महाप्राण निराला

की जन्मशती के समापन (बसंत पंचमी, 12 फरवरी 1997) के अवसर पर उनकी तीन कविताएं-

तोड़ती पत्थर

वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर
वह तोड़ती पत्थर।
कोई न छायादार
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार,
श्याम तन, भर बंधा यौवन,
नत नयन, प्रिय कर्म रत मन।
गुरु हथौड़ा हाथ,
करती बार-बार प्रहार --
सामने तरु मालिका अट्टालिका, प्राकार।
चढ़ रही थी धूप
गर्मियों के दिन
दिवा का तमतमाता रूप।
उठी झुलसाती हुई लू
रुई ज्यों जलती हुई भू
गर्द चिनगी छा गयी,
प्रायः हुई दुपहर,
वह तोड़ती पत्थर।
देखते देखा मुझे तो एक बार
उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार।
देखकर कोई नहीं,
देखा मुझे उस दृष्टि से
जो मार खा रोयी नहीं।
सजा सहज सितार,
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार।
एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर,
ढुलक माथे से गिरे सीकर,
लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा --
'मैं तोड़ती पत्थर!'

जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ, आओ, आओ!

जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ, आओ, आओ!
आज अमीरों की हवेली
किसानों की होगी पाठशाला,
धोबी, पासी, चमार, तेली
खोलेंगे अंधेरे का ताला,
एक पाठ पढ़ेंगे, टाट बिछाओ।
यहां जहां सेठ जी बैठे थे
बनिये की आंख दिखाते हुए,
उनके ऐंठाये ऐंठे थे
धोखे पर धोखा खाते हुए,
बैंक किसानों का खुलवाओ।
सारी सम्पत्ति देश की हो,
सारी आपत्ति देश की बने,
जनता जातीय वेश की हो,
वाद से विवाद यह ठने,
काटा कांटे से कढ़ाओ।

राजे ने अपनी रखवाली की

राजे ने अपनी रखवाली की;
किला बनाकर रहा,
बड़ी-बड़ी फौजें रखीं।
चापलूस कितने सामन्त आये।
मतलब की लकड़ी पकड़े हुए।
कितने ब्राह्मण आये
पोथियों में जनता को बांधे हुए
कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाये,
लेखकों ने लेख लिखे,
ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे,
नाट्यकलाकारों ने कितने नाटक रचे,
रंगमंच पर खेले।
जनता पर जादू चला राजे के समाज का।
लोक-नारियों के लिए रानियां आदर्श हुईं।
धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ।
लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर।
खून की नदी बही।
आंख-कान मूंदकर जनता ने डुबकियां लीं।
आंख खुली -- राजे ने अपनी
रखवाली की।

जर्मन जनता के कवि बर्तोल्त ब्रेख्त की जन्मतिथि (10 फरवरी) के अवसर पर

बर्तोल्त ब्रेख्त की कविताएं

शासन करने की कठिनाई

1. मंत्रीगण हरदम कहते रहते हैं जनता से
कि कितना कठिन होता है शासन करना।
बिना मंत्रियों के
फसल जमीन में ही धंस जाती,
बजाय ऊपर आने के।
न ही एक टुकड़ा कोयला बाहर
निकल पाता खदान से
अगर चांसलर इतना बुद्धिमान नहीं होता।
प्रचारमंत्री के बगैर
कोई लड़की कभी राजी ही न होती
गर्भधारण के लिए।
युद्धमंत्री के बिना
कभी कोई युद्ध ही न होता।
और कि सचमुच सूरज उगेगा भोर में
बिना फ्यूहरर की आज्ञा के
बहुत संदेहास्पद है,
और अगर यह उगा भी तो,
गलत जगह ही होगा।
2. ठीक उतना ही कठिन है, ऐसा वे हमें बताते हैं
चलाना एक फैक्टरी को।
बिना उसके मालिक के
दीवारें ढह पड़ेंगी और मशीनों में जंग लग जायेगी,
ऐसा वे कहते हैं।
भले ही एक हल बना लिया जाये कहीं पर
यह कभी नहीं पहुंचेगा खेत तक
बिना उन धूर्तता भरे शब्दों के
जिन्हें फैक्टरी मालिक लिखता है किसानों के लिए :
कौन उन्हें बतायेगा उनके सिवा कि हल मौजूद हैं?
और क्या होगा जागीर का अगर जमींदार न हों?
निश्चय ही वे बो देंगे राई जहां बोना था आलू।
3. अगर शासन करना सरल होता
तो कोई जरूरत न होती फ्यूहरर जैसे अन्तःप्रेरित
दिमाग वालों की।
अगर मजदूर जानते कि कैसे चलायी जाती है मशीन
और
किसान जोत-बो लेते अपने खेत घर बैठे ही
तो जरूरत ही न होती किसी फैक्टरी मालिक या जमींदार
की
यह तो सिर्फ इसीलिए है कि वे सब हैं ही इतने जाहिल
कि जरूरत होती है इन थोड़े से समझदार लोगों की।
4. या यह भी तो हो सकता है
कि शासन करना इतना कठिन है ही इसीलिए
कि ठगी और शोषण के लिए जरूरी है
कुछ सीखना-समझना।

(* फ्यूहरर - हिटलर)

आठ हजार गरीब लोगों का नगर के बाहर इकट्ठा होना

'आठ हजार से अधिक बेरोजगार खानकर्मी, अपने बीवी–बच्चों समेत बुडापेस्ट के बाहर साल्गोटार्जन रोड पर जमा हो रहे हैं। उन्होंने अपने अभियान में पहली दो रातें बिना कुछ खाये–पिये ही गुजार दी है। उनके शरीर पर बेहद नाकाफी जीर्ण–शीर्ण कपड़े हैं। देखने में वे बस हड्डियों के ढांचे ही भर हैं। अगर वे खाना और काम पाने में नाकाम रहे, तो उन्होंने कसम खा रखी है कि वे बुडापेस्ट पर धावा बोल देंगे, भले ही इससे खून–खराबा ही क्यों न शुरू हो जाये, उनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बुडापेस्ट क्षेत्र में सैनिक बल तैनात कर दिये गये हैं, तथा उन्हें सख्त आदेश दे दिये गये हैं कि अगर लेशमात्र भी शांति भंग हो तो वे अपने आग्नेयास्त्र इस्तेमाल करें।'

हम जा पहुंचे सबसे बड़े शहर में
हममें से 1000 भूख से पीड़ित थे
1000 के पास खाने को कुछ नहीं था
1000 को खाना चाहिए था।
जनरल ने अपनी खिड़की से देखा
तुम यहां मत खड़े हो, वह बोला
घर चले जाओ भले लोगों की तरह
अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो लिख भेजो।
हम रुक गये, खुली सड़क पर :
'हम हल्ला मचायें इसके पहले
वे हमें खिला देंगे।'
लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया
जबकि हम देखते रहे उनकी धुंवा देती
चिमनियों को।
लेकिन आ पहुंचा फिर वह जनरल।
हमने सोचा : आ गया हमारा खाना।
जनरल बैठ गया मशीनगन के ऊपर
और पकाया जो था वह इस्पात।
जनरल बोला : बहुत भीड़ लगा रखी है
तुम लोगों ने
और गिनने लगा आगे बढ़कर।
हम बोले : बस इतने ही जो तुम्हारे सामने हैं
कुछ भी नहीं है आज खाने को।
हम नहीं बना सके अपनी झोपड़-पट्टी
हम नहीं साफ कर सके फिर से अपनी कमीज़ें
हमने कहा : अब हम और इन्तजार
नहीं कर सकते।
जनरल बोला : जाहिर है।
हमने कहा : लेकिन हम सभी मर नहीं सकते
जनरल बोला : क्यों नहीं?
हालात गर्म हो रहे हैं, शहर के लोगों ने कहा
जब सुनाई दी उन्हें पहली गोली की आवाज।

इंसाफ जनता की रोटी है

इंसाफ जनता की रोटी है
जिस तरह रोटी की रोज जरूरत है
उसी तरह न्याय की भी
बल्कि इसकी जरूरत दिन में कई बार होती है।
काम करते हुए, सुबह से रात तक
बुरे समय में, और अच्छे समय में
लोगों को पर्याप्त मात्र में
रोजाना न्याय की स्वास्थ्यवर्धक
रोटी की जरूरत होती है।
चूंकि यह न्याय की रोटी का मामला है,
यह अति महत्वपूर्ण है
कि कौन दोस्त इसे सेंकेगे?
दूसरे की रोटी कौन सेंकता है
दूसरे की रोटी की तरह ही
न्याय की रोटी भी
जनता द्वारा सेंकी जानी चाहिए।
पर्याप्त, स्वास्थ्यवर्धक, रोजाना।

बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कैसे किया ?

(तीसरी किश्त)

देर करना घातक है

सरकार अपनी वफादार टुकड़ियों को शहर की ओर कूच कराने के लिए बदहवासी के साथ कोशिश कर रही थी। 23 अक्टूबर को तीसरे पहर करेन्स्की ने अपने सर्वोच्च कमाण्डरों से गुप्त रूप से मुलाकात की। वे इस बात पर राजी हुए कि अगले दिन बोल्शेविकों पर हमला बोल दिया जाये। उन्होंने सैन्य क्रान्तिकारी समिति पर आपराधिक मुकदमें शुरू करने, लेनिन सहित जुलाई के उभार के बाद रिहा हुए अन्य बोल्शेविकों को गिरफ्तार करने और बोल्शेविक अखबारों को बन्द करने की चाल चली।

अगले दिन तड़के ही करेन्स्की और अस्थायी सरकार ने हमला बोल दिया। स्मोल्नी स्थित सोवियत सदर मुकाम पर शहर के बाहरी इलाकों में टुकड़ियों की हरकतों के खतरनाक संकेत और करेन्स्की द्वारा अपनी वफादार टुकड़ियों को गोलबंद करने की उन्मत्त कोशिशों की रिपोर्टें मिलनी शुरू हो गयी थी। भोर के समय फौजी कैडटों और अफसरों के एक दस्ते ने बोल्शेविकों के मुख्य छापेखाने पर कब्जा कर लिया और उस दिन के अखबारों को जब्त कर लिया।

गश्ती कैडेटों ने मजदूरों के जिलों को शहर के केन्द्र से अलग-थलग करने के लिए नेवा नदी पर बने पुलों को सुनियोजित ढंग से अपने कब्जे में कर लिया। गश्ती कैडेटों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने और सड़कों के नुक्कड़ों पर मजमा लगाये लोगों को तितर-बितर करने के प्रयास में शहर के अन्दर भी मार्च किया।

जवाबी कार्रवाई के तौर पर, सैनिक क्रान्तिकारी समिति ने रेजिमेण्टल समितियों और कमिसारों को आदेश दिया कि वे अपनी रेजिमेण्टों को युद्ध के लिए तैयार रखें और अगले निर्देश का इन्तजार करें। सै.क्रा.स. ने लाल रक्षकों के हेडक्वार्टर स्टाफ को आदेश दिया कि 1500-2000 मजदूरों को स्मोल्नी भेज दें। अन्य टुकड़ियों को यह आदेश दिया गया कि वे अपने शहर के मुख्य ठिकानों पर कब्जा कर लें, कारखानों की सुरक्षा के बंदोबस्त करें और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने के लिए सेनाओं को एकत्र करें। सेना की एक इकाई लितोव्स्की गार्ड्स ने, जिसका नेतृत्व अब बोल्शेविक कर रहे थे, छापेखाने पर फिर से कब्जा कर लिया।

जनता उठ खड़ी हुई। 24 अक्टूबर को तीसरा पहर शुरू होते ही हथियारबंद मजदूर और सिपाही आदेश लेने के लिए स्मोल्नी की ओर रवाना हो गये। लाल रक्षकों और अन्य हथियारबंद मजदूरों को जुलाई के दिनों की याद ताजा थी जब सरकार पुलों को जाम करने और सर्वहारा जिलों को अलग-थलग करने में कामयाब हो गयी थी। इस बार वे बिना मौका चूके पुलों की ओर चल दिये जिससे उन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे कैडटों का मुकाबला किया जा सके।

इस बार फिर विबोर्ग ने बाजी मारी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार विबोर्ग के लाल रक्षकों ने "अपनी पहलकदमी पर... लितीनी, सेम्सोनीव्स्की और ग्रेनेदेर्स्की पुलों को अपने कब्जे में कर लिया।" सैन्य क्रान्तिकारी समिति द्वारा लितीनी भेजे गये एक कमिसार ने पाया कि पुल का एक छोर पहले ही बोल्शेविकों के प्रति वफादार सेना की एक टुकड़ी ने और दूसरा छोर लाल रक्षकों ने अपने कब्जे में कर रखा था। विबोर्ग को शहर से जोड़ने वाले पुलों को आनन-फानन में रिनॉल्ट वर्क्स और पारवियेनेन वर्क्स के लाल रक्षकों ने चालू कर दिया। बेन्ज वर्क्स के लाल रक्षक एक बख्तरबंद गाड़ी, जिसकी मरम्मत उन्होंने खुद की थी, पर सवार होकर एक अन्य पुल पर कब्जा करने के लिए रवाना हो गये।

लेकिन, जबकि निर्णायक संघर्ष की घड़ी करीब आ रही थी, सत्ता पर कब्जा करने के लिए जनता को जरूरी नेतृत्व अभी तक नहीं दिया गया था। 24 तारीख को लगातार लेनिन अपने गुप्त ठिकाने से आक्रमण करने के लिए पार्टी का आह्वान कर रहे थे। शाम को छह बजे इस बारे में लिखा गया उनका अन्तिम नोट इस तरह शुरू होता है :

"कामरेडो, मैं ये पंक्तियां 24 अक्टूबर की शाम को लिख रहा हूं। परिस्थिति बेहद, बेहद गम्भीर है। वास्तव में अब यह एकदम स्पष्ट हो गया है कि बगावत में देर करना घातक होगा।

"अपनी पूरी ताकत के साथ मैं कामरेडों का आह्वान करता हूं कि वे इसे समझें कि हर चीज एक बारीक सूत के सहारे टिकी हुई है; कि हम ऐसी समस्याओं में उलझे हुए हैं, जिनका समाधान सम्मेलनों और कांग्रेसों (यहां तक कि सोवियतों की कांग्रेस द्वारा भी नहीं) द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि इसका समाधान लोगों द्वारा, जनता द्वारा, हथियारबंद लोगों के संघर्ष द्वारा किया जाना है।

"कार्निलोवपंथियों द्वारा किये गये बुर्जुआ आक्रमण और वर्खोव्स्की के हटाये जाने ने यह दिखा दिया है कि हम कतई इंतजार नहीं कर सकते। हमें किसी भी कीमत पर इसी शाम, इसी रात पहले अफसर कैडटों को निशस्त्र करके (यदि वे प्रतिरोध करें तो उन्हें हराकर) सरकार को गिरफ्तार कर लेना है और आगे ही बढ़ते जाना है।

"हम कतई इंतजार नहीं कर सकते। हम सब कुछ खो सकते हैं।...

"सत्ता किसके हाथ में आ सकती है?

"फिलहाल यह महत्वपूर्ण नहीं है। सैन्य क्रान्तिकारी समिति को यह तय करने दीजिए या फिर किसी अन्य संस्था को,....

"सत्ता पर कब्जा करना बगावत का काम है, इसका राजनीतिक मकसद कब्जे के बाद स्पष्ट हो जायेगा।

"25 अक्टूबर के अनिश्चित वोटों (यानी सोवियतों की कांग्रेसें [4]) का इंतजार करना महाविपदा के समान होगा। यह महज एक खानापूरी होगी। लोगों का यह अधिकार है और इसके लिए वे कर्तव्यबद्ध हैं कि ऐसे सवालों का निर्णय वे वोट से नहीं बल्कि ताकत के जरिये करें।....

"सरकार लड़खड़ा रही है। उसका अनिवार्य रूप से हर कीमत पर काम तमाम कर देना चाहिए।"

"कार्रवाई में देर घातक है।"

(लेनिन की संकलित रचनाएं, खण्ड 26, 'केन्द्रीय समिति को पत्र', पृष्ठ 234-235)

कुछ ही घण्टों बाद लेनिन ने अपने तईं यह निर्णय लिया कि उन्हें स्मोल्नी जाना चाहिए और वे अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर 24 अक्टूबर की आधी रात को वहां पहुंच गये।

वह कौन सी बात थी जिसके कारण लेनिन इतने जोर देकर अत्यन्त दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रहे थे? कौन सी चीज दांव पर लगी थी?

या तो इरादतन या फिर आदत और स्वतःस्फूर्तता के वशीभूत होकर बोल्शेविक नेतृत्व के अन्दर यह गम्भीर प्रवृत्ति हावी थी कि कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लेने के बाद और कुछ सुरक्षात्मक उपाय कर लेने के बाद सोवियतों की कांग्रेस सम्पन्न हो जाने तक इन्तज़ार किया जाये। यह रणनीति अस्थायी तौर पर क्रान्ति को कुचलने या नेस्तनाबूद कर देने की सरकार की क्षमता के रास्ते में रोड़े तो अटका सकती थी लेकिन यह अपरिहार्य रूप से गतिरोध में परिणत हो जाती। यह मुमकिन था कि सरकार शीत प्रासाद में सिमटकर वार्तालाप और मध्यस्थता करने के वायदे करते हुए तब तक समय गुजरने देती जब तक वह अपनी फौजों को फिर से हमला बोल देने के लिए इकट्ठा न कर लेती।

24 तारीख की घटनाओं के दौरान पहलकदमी जनता के हाथ में थी। लेकिन देर करने से हालात बदल सकते थे और पहलकदमी सरकार के हाथ में जा सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्रान्तिकारी सेनाओं की कार्रवाइयों ने अभी तक इतनी अधिक संख्या में लोगों को बाहर नहीं निकाला था कि वे फौजी रूप से सक्रिय होकर सत्ता पर कब्जा कर सकें।

दोनों पक्षों -- एक ओर अपनी स्थापित सेनाओं के साथ सरकार और दूसरी ओर जनता, जिसने अपनी सेनाओं को युद्ध की आग में झोंक दिया था -- में अपनी रिजर्व सेनाओं में बढ़ोत्तरी के लिये होड़ मची हुयी थी। जनता के लिए रिजर्व सेनाओं का मतलब था -- विशाल जनसमुदाय, जो केवल तभी सक्रिय हो सकता था जब उसे सत्ता पर कब्जे के सशस्त्र संघर्ष में सफलता की उम्मीद दिखायी दे। सरकार के लिए इसका मतलब था अधिक से अधिक वफादार टुकड़ियों को अपने कमान में रखना।

यहां यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि स्थापित सेनाओं के लिए यह फायदे की स्थिति होती है कि वे संगठित और अनुशासित होती हैं। जो भी हो, आखिरकार वह एक सेना होती है। ऐसी सेना को परास्त करने के लिए उसे पर उस समय निर्मम प्रहारों की आवश्यकता होती है जब वह बिखरी हुई हो और एक दूसरे से अलग-थलग पड़ गयी हो और ऐसा करते समय व्यापक जनता को इस संघर्ष में उतारना चाहिए। इसीलिए लेनिन ने इस बात पर बिल्कुल ठीक जोर दिया कि देर करना घातक है। यही वजह थी कि उन्होंने पार्टी को आक्रमण के लिए तैयार करने के लिए इतना तीखा संघर्ष किया। इसीलिए इस बात का इतना महत्व है जिसने संघर्ष में सफलता दिलायी।

निष्कर्ष: एक नया सवेरा उगा

आधी रात को लेनिन का स्मोल्नी पहुंचना आम बगावत के लिये उत्प्रेरक बन गया। अब दुगुने जोश के साथ आक्रमण शुरू हुआ। पेत्रोग्राद शहर के महत्वपूर्ण ठिकानों पर तेजी के साथ और सुव्यवस्थित ढंग से कब्जे की कार्रवाई आगे बढ़ी। सुबह एक बजकर पच्चीस मिनट पर विबोर्ग और बाल्टिक बेड़े के लाल रक्षकों, केन्जोम रेजिमेण्ट के क्रान्तिकारी सैनिको और क्रान्तिकारी मल्लाहों की एक टुकड़ी ने केन्द्रीय डाकघर को अपने कब्जे में कर लिया।

दो बजे भोर में लाल रक्षकों और क्रान्तिकारी सैनिकों की दो मजबूत टुकड़ियों ने निकोलेव्स्की और बाल्टिक रेलवे स्टेशनों पर कब्जा जमा लिया। विद्रोहियों के लिये इन पर कब्जा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर के बाहर से इसी रास्ते से सरकार अतिरिक्त टुकड़ियों को भेज सकती थी। निकोलेव्स्की स्टेशन के तारघर को प्रतिक्रान्तिकारियों के चंगुल से आजाद कराया तथा उनकी टुकड़ी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे डिपो और अमेरिकन ब्रिज के पास के वर्कशाप पर भी कब्जा कर लिया गया और उसपर सुरक्षा का घेरा कस लिया गया। लगभग इसी समय अन्य क्रान्तिकारी टुकड़ियों ने शहर के बिजलीघर पर भी कब्जा जमा लिया।

भोर में लगभग तीन बजे पावलोव्स्की रेजिमेण्ट के क्रान्तिकारी सैनिकों ने शीत प्रासाद के निकट की मुख्य सड़कों के चारों ओर घेराबन्दी कर ली और सहायता की तलाश में प्रासाद से बाहर निकल रहे कैडटों से भरी कार को रोक लिया। साढ़े तीन बजे आरोरा जलपोत पर तीखे संघर्षों के बाद सिपाहियों ने निकोलेव्स्की पुल के पास लंगर डाल दिया, पुल को विद्रोहियों के पक्ष में कब्जे मे ले लिया, आवागमन को चालू कर दिया और इसकी सुरक्षा कर रहे कैडेटों को तितर-बितर कर दिया।

सुबह छह बजे समुद्री रक्षकों की एक टुकड़ी, जिसमें 40 आदमी थे, केन्जोम रेजिमेण्ट के साथ मिलकर गार्ड रूम के रास्ते से स्टेट बैंक के भीतर घुस गयी और उस पर कब्जा कर लिया।

मध्य रात्रि से लेकर एकदम सुबह तक सैन्य क्रान्तिकारी समिति सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों और मुख्य रणकौशलात्मक ठिकानों पर अविराम सेनाओं को भेजती रही। इन हमलों की संख्या और व्यापकता इतनी ज्यादा थी कि सरकार को यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि इन हमलों से कहां और कैसे मुकम्मिल ढंग से बचाव किया जाये। और जिस तरीके से विद्रोहियों ने संचार सम्पर्क स्थापित करने, सेनाओं और रसद की आवाजाही की सरकारी क्षमता को निशाना बनाया था उससे दुश्मन लड़खड़ा गया था और इसने पहलकदमी को जनता के हाथों में बनाये रखा।

युद्ध में पहलकदमी का सवाल जिन्दगी और मौत का सवाल है। माओ ने लिखा है कि "पहलकदमी का मतलब है किसी सेना की कार्रवाई की आजादी। कार्रवाई की आजादी किसी सेना का प्राणतत्व है और एक बार यदि यह खो जाये तो समझ लेना चाहिए कि वह सेना पराजय या विनाश के कगार पर खड़ी है।"

यहां तक कि हथियारों के मामले में निम्न स्तर की कोई सेना पहलकदमी को अपने कब्जे में रखकर अपने से बेहतर हथियारबन्द दुश्मन को निष्क्रिय स्थिति में डाल सकती है। पहलकदमी हासिल करने का एक मुख्य तरीका आकस्मिक आक्रमण है। 24 अक्टूबर की झड़पों के बावजूद जब बोल्शेविकों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और कई महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर हमले शुरू किये तो यह एकदम स्पष्ट हो गया था कि सरकारी सेनाएं इसके लिए तैयार नहीं थी।

विद्रोही सर्वहाराओं ने साहसिकता और आकस्मिक आक्रमण से पहलकदमी को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने न केवल आम बगावत को कुचल देने की क्षमता को पंगु बना दिया बल्कि व्यापक जनसमुदाय को सक्रिय करने के लिए और उन्हें "हथियारबन्द जनता" का हिस्सा बनाने के लिए परिस्थितियां भी तैयार कीं।

दोपहर होने के पहले तक सरकारी सेनाएं शीतप्रासाद के दुर्ग और पेत्रोग्राद फौजी एरिया के मुख्यालय के अन्दर धकेल दी गयीं। करेन्स्की अमेरिकी और ब्रिटिश सुरक्षा के घेरे में अपनी वफादार टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए भागा। इस बीच सड़कों पर मजदूरों का रेला लग गया था। सुबह दस बजे सैन्य क्रान्तिकारी समिति ने रूसी जनता के नाम निम्नलिखित घोषणा जारी की :

"अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका गया है। राज्यसत्ता मजदूरों और सिपाहियों की पेत्रोग्राद सोवियत के सर्वोच्च अंग -- सैन्य क्रान्तिकारी समिति, जो पेत्रोग्राद के सर्वहारा और गैरिसन की अगुवा है -- को हस्तान्तरित हो गयी है।"

"उस उद्देश्य की सफलता, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, यानी तत्काल एक जनवादी शान्ति की स्थापना, जमीन्दारी का उन्मूलन, उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना और एक सोवियत सरकार का गठन, सुनिश्चित है।"

"मजदूरों, सिपाहियों और किसानों की क्रान्ति जिन्दाबाद!"

इस पर लेनिन ने हस्ताक्षर किये थे और तार के जरिये इसे सभी औद्योगिक केन्द्रों को भेज दिया गया। इसने जनउभार को और व्यापक बनाने में चिन्गारी का काम किया। अब लेनिन ने शीत प्रासाद पर आक्रामक कार्रवाई कर उस पर कब्जा जमाने और अस्थायी सरकार को गिरफ्तार करने के लिए पूरा जोर लगा दिया।

टिप्पणियां

4. सोवियतों की कांग्रेस प्रत्येक जिले और शहर के सोवियतों के एक अखिल रूसी प्रतिनिधियों का समूह थी।

(अगले अंक में जारी)

स्वत्वाधिकारी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वानी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
सम्पादक : डा. दूधनाथ । सम्पादकीय पता : द्वारा, ओ.पी. सिन्हा, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, लखनऊ – 226 007 सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।